प्रकाशन तिथि : 20 मार्च, 2021 * वर्ष-30, पृष्ठ संख्या 60, अंक-3

राजस्थान सुजस

2021-22 सर्वहितकारी बजट

प्रदेश में पहली बार पेपरलैस बजट

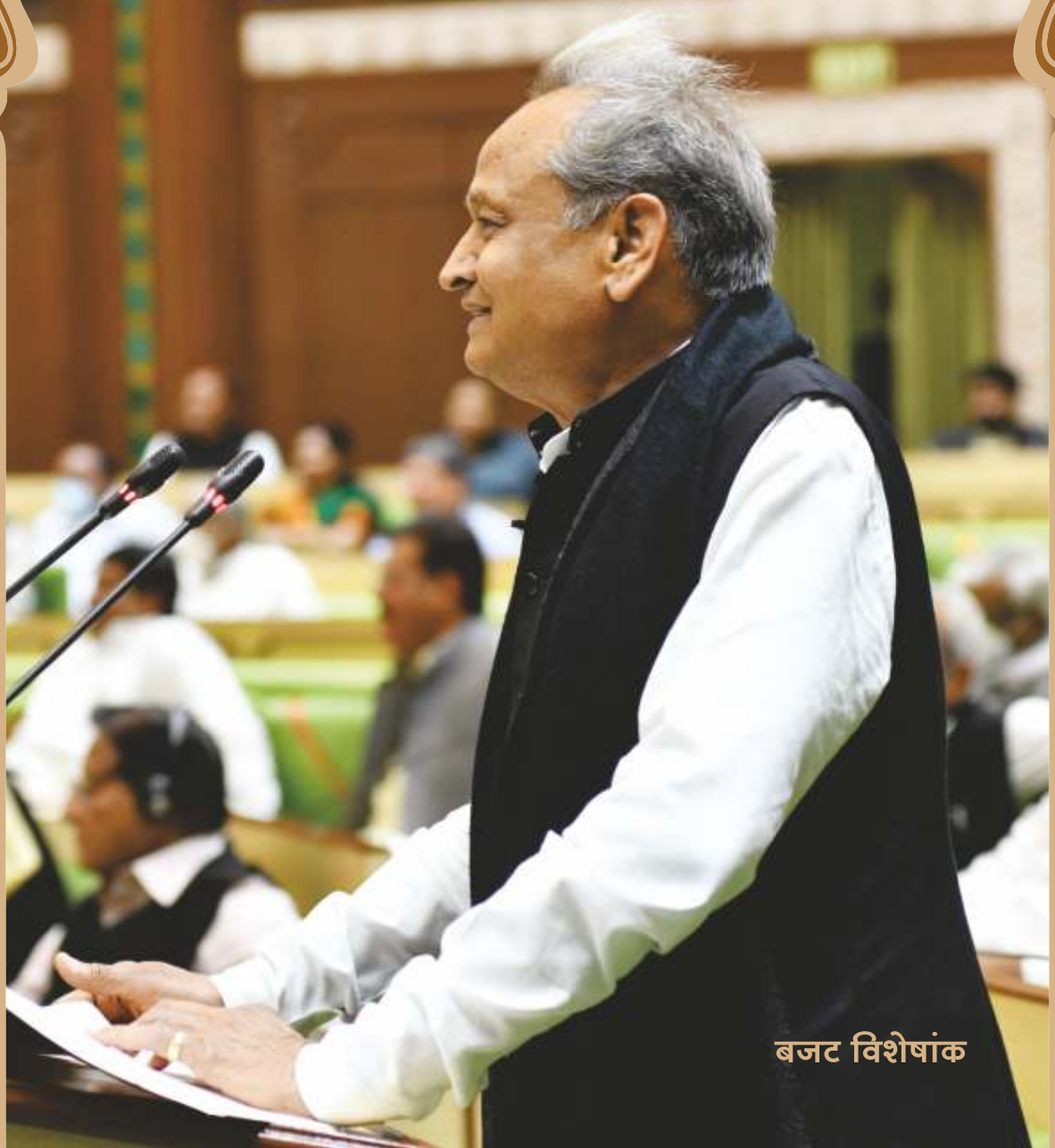

बजट विशेषांक

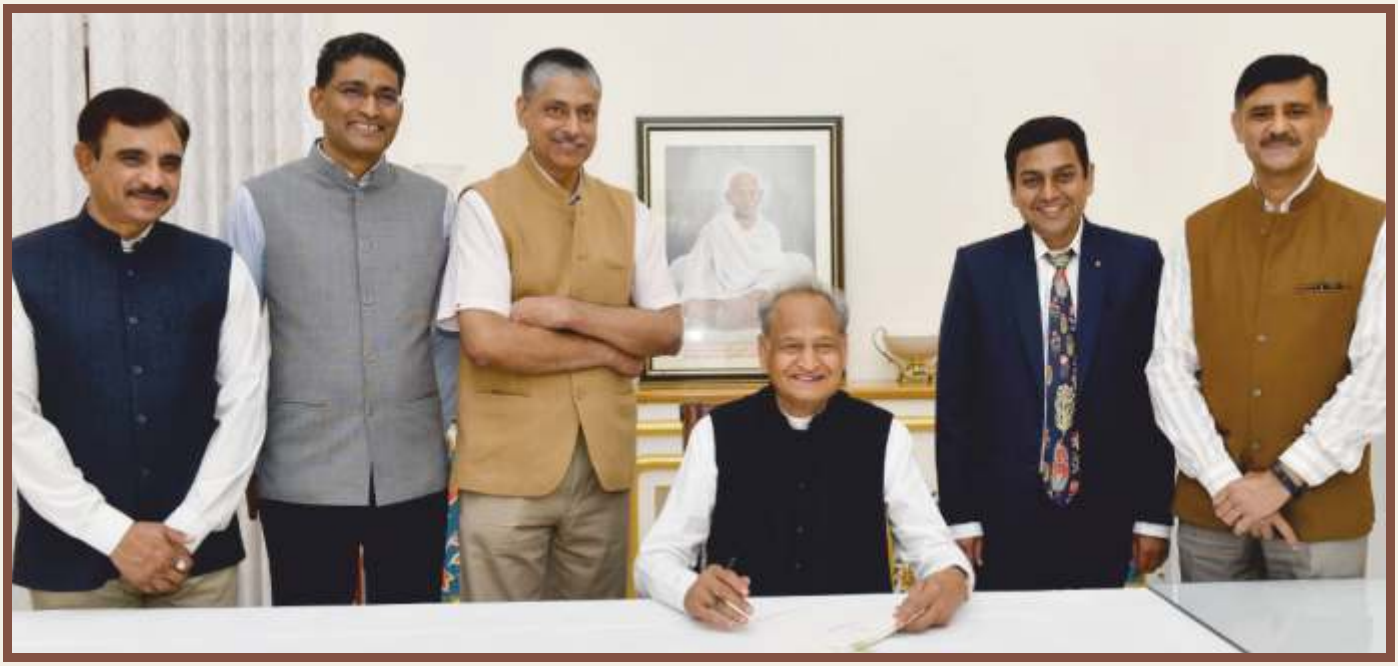

बजट 2021–22
को अंतिम रूप

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य बजट को अन्तिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) श्री टी. रविकांत, शासन सचिव वित्त (बजट) डॉ. पृथ्वीराज, विशिष्ट सचिव वित्त (व्यय) श्री सुधीर कुमार शर्मा एवं निदेशक (बजट) श्री शरद मेहरा मौजूद थे।

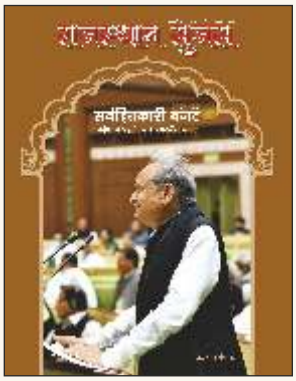

प्रधान सम्पादक
महेन्द्र सोनी, आईएएस
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

•

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

•

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

•

कला
विनोद कुमार शर्मा

•

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिण्ट 'ओ' लैण्ड

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 30 अंक : 03 मार्च, 2021

इस अंक में

बजट 2021-22 ... 02
सम्पादकीय 04
कोरोना प्रबंधन 06
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं 08
सड़क सुरक्षा 12
शिक्षा 12
युवा एवं रोजगार 15
कृषक एवं पशुपालक कल्याण 16
उद्योग 19
सामाजिक सुरक्षा 20
पेयजल-जल संसाधन 29
ऊर्जा 33
वन एवं पर्यावरण 33
पर्यटन, कला एवं संस्कृति 34
कानून व्यवस्था 36
सुशासन 38
कर प्रस्ताव 40

कोविड टीकाकरण

59

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

बजट 2021-22 बहस पर जवाब में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणाएं

47

ऐतिहासिक, साहसिक और सर्वांगीण विकास को समर्पित प्रदेश का बजट

52

05

राज्य सरकार का सर्वहितकारी बजट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में 24 फरवरी को वर्ष 2021–22 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया यह बजट सर्वहितकारी है। इस बजट को राज्य सरकार ने प्रदेश की निरन्तर प्रगति के संकल्प के साथ प्रस्तुत किया है। बजट में हर वर्ग के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है।

प्रदेश में पहली बार बजट पेपरलैस प्रस्तुत किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। कोरोना प्रबंधन के लिए बजट में विशेष कोविड पैकेज की व्यवस्था कर राज्य में सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है।

इस बार का बजट भाषण राज्य में प्रस्तुत अब तक के बजट भाषणों में सबसे अधिक समय का रहा है। यह बजट भाषण 2 घंटे 48 मिनट का रहा। इस बार का बजट चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार और कर राहत पर केन्द्रित रहा। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की सेहत की सुरक्षा के साथ हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का दिग्दर्शन बजट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

राज्य सरकार के ध्येय वाक्य जनकल्याण ही प्रतिबद्धता और जनकल्याण ही प्राथमिकता के अनुरूप अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के समावेश के साथ लोगों के कारोबार व उद्योगों को संबल और आमजन को यह बजट राहत देने वाला है। इसमें राज्य के विकास के साथ आधारभूत ढांचे को मजबूती देने वाली योजनाएं भी शामिल हैं।

राजस्थान सुजस का यह अंक बजट पर आधारित है। इस अंक में मुख्यमंत्री का बजट भाषण, नवीन योजनाओं की जानकारी और बजट के विश्लेषण पर आधारित आलेख का समावेश किया गया है। "राजस्थान सुजस" सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipronline@rajasthan.gov.in के साथ जन सूचना पोर्टल पर भी उपलब्ध है। रंगों के पर्व होली की शुभकामनाओं के साथ सुजस का मार्च माह का अंक आपके हाथों में है।

(महेन्द्र सोनी)
आई.ए.एस.
आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क

बजट 2021-22

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री, राजस्थान

'पलट देते हैं
हम मौजे-हवादिस
अपनी जुर्रत से,
कि हमने
आंधियों में भी
चिराग अक्सर
जलाये हैं।'

माननीय अध्यक्ष महोदय,

- आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश में पहली बार पेपरलैस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक कदम है।
- बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करता है। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार होती है। हमारी सोच है कि प्रदेश के किसान भाइयों, व्यापारियों–उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वंचित वर्गों आदि सभी तबकों को साथ लेकर हम प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बना सकें।

कोरोना प्रबंधन

- आज जब मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्ययोजना रखने को उपस्थित हुआ हूं, तब मुझे सबसे पहले यह ध्यान आ रहा है कि किस तरह कोविड–19 महामारी ने प्रदेश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। इस बजट को बनाते वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि इन मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद भी, प्रदेश के विकास के लिए संसाधनों की कमी ना रहे। हम यह संकल्प ले रहे हैं कि दूरगामी सोच के साथ, आर्थिक संसाधन जुटाये जाने के अभिनव प्रयास किये जायेंगे और हमेशा की तरह, इस चुनौती को भी एक अवसर में बदलेंगे। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामप्रसाद बिस्मिल के शब्दों में–

'पलट देते हैं हम मौजे–हवादिस अपनी जुर्रत से,
कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाये हैं।'

- पिछला एक साल हम सबके लिए बहुत कठिन रहा है। अपने सार्वजनिक जीवन में इससे मुश्किल दौर शायद ही हमने कभी देखा हो। हमारे द्वारा राज्य में कोरोना की शुरूआत से ही निरंतर मॉनिटरिंग–माइक्रोप्लानिंग पर जोर दिया गया और **'राजस्थान सतर्क है'** की पहल के साथ कोविड–19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल प्रबंधन किया गया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है। हमारे **भीलवाड़ा**

एवं रामगंज मॉडल को देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया।

- मैंने स्वयं Video Conferencing के माध्यम से राजनीतिक दलों, विधायकगण, धर्मगुरुओं, उद्योगपतियों, NGOs, चिकित्साकर्मियों, मीडिया बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों आदि सहित सभी Stakeholders से 109 बार निरंतर संवाद किया तथा किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रह जाये, इसके लिए संबंधित विभागों के साथ 210 से अधिक कोविड–समीक्षा बैठकें की। इस बेहतरीन प्रबंधन के चलते, कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए हमने प्रदेश में Health Infrastructure को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए, जांच क्षमता शून्य से बढ़ाकर 70 हजार प्रतिदिन की गयी। इसके साथ ही, मानव धर्म निभाते हुए इस संकट काल में हमारा संकल्प था कि **'कोई भूखा न सोये'।** प्रदेशवासियों के सहयोग से हम इसे पूरा करने में सफल रहे। हमने Post Covid Management पर भी पूरा फोकस किया है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि अब हम टीकाकरण अभियान में भी पूरी तैयारी और तत्परता से अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना कम हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अत: मेरा समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह है कि कोरोना प्रोटाकॉल की पालना अवश्य करें।
- यद्यपि अब कोरोना महामारी का प्रभाव कम हुआ है परन्तु समाज के हर तबके ने कोरोना की मार सही है। थड़ी–ठेले लगाने वालों व छोटे व्यापारियों का कामकाज प्रभावित हुआ, गरीब एवं असहाय लोगों की रोजी–रोटी पर संकट आया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाये। इसके बावजूद भी हर प्रदेशवासी ने धैर्य एवं सहयोग का परिचय दिया। आमजन की इस पीड़ा को अनुभव करते हुए मैं, **एक विशेष कोविड पैकेज** की घोषणा करता हूं–
  - हमने इस महामारी काल में 33 लाख असहाय, निराश्रित (Destitute) व मजदूर परिवारों को 3 हजार 500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 1 हजार 155 करोड़ रुपये की, DBT के माध्यम से सहायता प्रदान की है। अब मैं, आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में एक–एक हजार रुपये की और सहायता राशि दो बार में देने की घोषणा करता हूं।

  - मैं, शहरी क्षेत्र के Street Vendors एवं Service Sector के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना** शुरू करने की घोषणा करता हूं। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
  - लघु उद्योगों को संबल देने के लिए **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना** का दायरा बढ़ाते हुए, आगामी वर्ष में 10 हजार नये लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है।
  - प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, केवल Project Appraisal के आधार पर बिना किसी शर्त के Seed Money के रूप में 5 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप सहायता राशि दिया जाना प्रस्तावित करता हूं।
  - कोरोना महामारी के कारण छात्र–छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हुई, जिससे यह वर्ष लगभग Zero Year हो गया है। विद्यार्थियों के Learning अन्तराल को पूर्ण करने, Learning Standards के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने तथा Class Room के प्रति सहज अनुभव करवाने के लिए Back to school कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। मैं, आगामी वर्ष में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क

School Uniform तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रमानुसार पूरक पाठ्य–पुस्तकें **नि:शुल्क** दिये जाने की घोषणा करता हूं। इन पर लगभग 470 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

- महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में सहरिया, कथौड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित करता हूं।

- कोरोना की इस कठिन परीक्षा की घड़ी के दौरान सभी प्रदेशवासियों ने जो अभूतपूर्व साहस, संयम, सहयोग और जिम्मेदारी दिखाई है, उसके लिए मैं, आज इस पूरे सदन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं।

- जैसा कहा गया है–

  'उद्यमेन हि सिद्धयन्ति, कार्याणि न मनोरथै:'

  अर्थात् कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। इसी भावना के साथ, हमारी सरकार ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखी, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। हमारी सरकार का मुख्य ध्येय **जनकल्याण ही प्रतिबद्धता, जनकल्याण ही प्राथमिकता** रहा है। इसी का सुफल है कि हमने 2 साल में ही **जनघोषणा** के आधे से अधिक वादों को पूरा किया है। अब हमारा प्रयास है कि विकास की इस गति को और बढ़ायें तथा जनता से किये गये वादों को पूरा कर, प्रदेश को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि **'पहला सुख निरोगी काया'** की अवधारणा पर काम करते हुए हमारी सरकार का पिछले दोनों व वर्तमान कार्यकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहा है। हमारे द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, नये मेडिकल कॉलेज व कोविड–प्रबंधन इत्यादि की सभी ने प्रशंसा की है। अब समय आ गया है कि हमारे द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किये गये कामों एवं नवाचारों को हम और आगे ले जायें। इसी कड़ी में, अब राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए **Rajasthan Model of Public Health (RMPH)** लागू किया जायेगा। इस मॉडल को प्रभावी बनाये जाने तथा सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से **Right to Health Bill** भी लाया जा रहा है। यह मॉडल जन–जन के लिए उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य मानदण्डों को प्राप्त करने का, देशभर में एक अनूठा उदाहरण पेश करेगा। इस मॉडल के माध्यम से Preventive Care, Primary Care व Curative Care को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भावना के अनुरूप लागू करने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं।

- अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी वर्ष से हम 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से, देश में पहली बार हमारे प्रदेश में **Universal Health Coverage** लागू करेंगे। इसके मायने हैं कि राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार, **आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना** के NFSA एवं SECC परिवारों के साथ–साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को नि:शुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर (अर्थात् लगभग 850 रुपये वार्षिक खर्च पर) सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में cashless इलाज हेतु 5 लाख रुपये तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

- जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसके करीब–करीब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मैं, शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। प्रथम चरण में, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जायेंगे।

- Public Health के महत्त्व को देखते हुए भविष्य में इस पर फोकस देने के लिए मैं, सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से **Public Health College** की स्थापना करने की घोषणा करता हूं।

- मैं, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए Hub and Spoke Model अपनाकर जांचों की संख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में 15 से बढ़ाकर 61, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में 37 से बढ़ाकर 95, उपजिला अस्पताल (Sub District Hospital) में 56 से बढ़ाकर 109 एवं जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 133 करने की घोषणा करता हूं।
- **निरोगी राजस्थान** की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए राज्य के चिकित्सालयों में विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–
  - **महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा** में 71 करोड़ रुपये की लागत से 205 बेड क्षमता का व **श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर** में 90 करोड़ रुपये की लागत से 300 बेड क्षमता के नवीन चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
  - **आरबीएम चिकित्सालय, भरतपुर** में 87 करोड़ रुपये की लागत से 250 बेड क्षमता के नवीन चिकित्सालय का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, भरतपुर में सुपर स्पेशियलिटी–न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी व कार्डियोलॉजी विभाग भी प्रारंभ किये जायेंगे।
  - **जिला चिकित्सालय, पाली** में 145 करोड़ रुपये की लागत से 380 बेड क्षमता, **जिला चिकित्सालय, चूरू** में 129 करोड़ रुपये की लागत से 370 बेड क्षमता व **जिला चिकित्सालय, बाड़मेर** में 126 करोड़ रुपये की लागत से 360 बेड क्षमता के चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
  - **मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर** में 17 करोड़ रुपये की लागत से नवीन डायग्नोस्टिक विंग का निर्माण करवाया जायेगा।
  - जयपुर के गणगौरी बाजार अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- अजमेर शहर के मध्य स्थित मेडिकल कॉलेज को कायड़ में स्थानान्तरित किया जायेगा, जिससे जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के विस्तार हेतु भूमि भी उपलब्ध हो सकेगी। इसके निर्माण में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

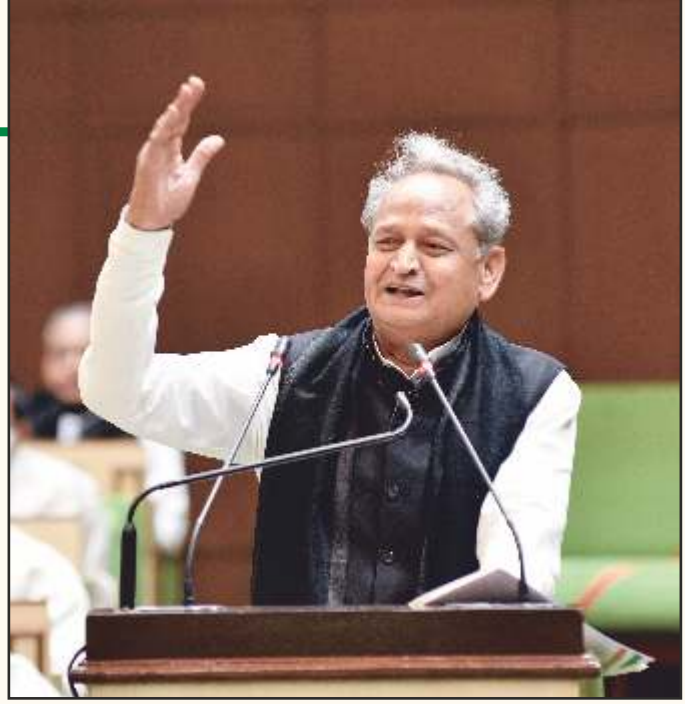

- प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं, घोषणा करता हूँ कि –
  - बालेरा, दुदाबेरी–बाड़मेर, धींगपुर (दांतारामगढ़)–सीकर, भाखरानी–जैसलमेर, सीनेर, डंडोली (सिवाना)–बाड़मेर, कसेड़, दौलतपुरा (सपोटरा), बींजवाड़िया (तिंवरी)–जोधपुर, कटोरी (हिण्डौन)–करौली, इंदावड़ तथा मोकलपुर (मेड़ता)–नागौर सहित राज्य में 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) खोले जायेंगे।
  - गुढ़ा कटला (बांदीकुई), बालाहेड़ी (महुआ)–दौसा, टमकोर (मण्डावा)–झुंझुनूं, गोगामेड़ी–हनुमानगढ़, मिर्जेवाला 17 जेड (सादुलशहर)–श्रीगंगानगर, खो–नागोरियान (बगरू)–जयपुर, लांगरा (सपोटरा), शेरपुर–करौली, अलावड़ा (रामगढ़)–अलवर, कैमरी (टोड़ाभीम), छोकरवाड़ा, पहाड़ी (कामां)–भरतपुर, जावाल–सिरोही, पादरू (सिवाना)–बाड़मेर, पांचौड़ी (खींवसर)–नागौर, नैनवां–बूंदी, खिरनी–सवाई माधोपुर, मरैना (राजाखेड़ा)–धौलपुर, बनेठा (उनियारा)–टोंक, जावदा (रावतभाटा)–चित्तौड़गढ़, सम–जैसलमेर, मादड़ी (झाड़ोल)–उदयपुर, हतुण्डी (ओसियां), पीलवा (लोहावट)–जोधपुर तथा चाणौद (सुमेरपुर)–पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित प्रदेश के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
  - बैजूपाड़ा–दौसा व रानोली (दांतारामगढ़)–सीकर में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मथानिया को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा व सांगानेर–जयपुर में नवीन सेटेलाइट अस्पताल बनाया जायेगा।
- शाहपुरा–जयपुर, फतेहपुर–सीकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- शाहपुरा–भीलवाड़ा, नोखा–बीकानेर, हिण्डौन–करौली, सागवाड़ा–डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर शहर (CHC) नीमकाथाना–सीकर, शिवगंज–सिरोही, बालोतरा–बाड़मेर व प्रतापनगर–जोधपुर के चिकित्सा संस्थानों को **जिला अस्पताल** में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- कुचामन सिटी, लाडनूं–नागौर, उदयपुरवाटी–झुंझुनूं हलैना–भरतपुर, मनियां (राजाखेड़ा)–धौलपुर व कोलायत–बीकानेर सहित 10 नवीन ट्रोमा सेन्टर खोले जायेंगे।
- 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु लगभग 206 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रोगी भार कम किये जाने के लिए कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना व जोधपुर में मण्डोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1 हजार बेड्स की वृद्धि की जायेगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप–स्वास्थ्य केन्द्रों को **Health and wellness centre** के रूप में विकसित कर 12 प्रकार की विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवायी जायेंगी। इसके लिए 11 हजार से अधिक **Community Health Officers (CHO)** की भर्ती की जा रही है।
- एक हजार आयुर्वेद औषधालयों को Health and wellness centre के रूप में विकसित किया जायेगा।
- अजमेर में **राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र** की स्थापना की जायेगी।

- मैं, माननीय विधायकगण का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने विधायक कोष से 2 वर्ष के लिए एक–एक करोड़ रुपये की राशि Health Infrastructure को मजबूत करने हेतु खर्च करने की सहमति दी। हमने 'मॉडल CHC' की रूपरेखा तैयार कर ली है। हम चाहेंगे कि माननीय विधायकगण अपने–अपने क्षेत्रों में एक CHC का चयन करें, जिसमें सुविधाओं का विस्तार कर **'मॉडल CHC'** बनायी जा सके।
- मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरिनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जायेगी। साथ ही, इसमें 500 बेड क्षमता के एवं मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में 650 बेड क्षमता के नवीन पीजी छात्रावासों का 102 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।
- जिला अस्पताल, पावटा–जोधपुर की बेड क्षमता को 150 से बढ़ाकर 300 किया जायेगा तथा आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु 25 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।
- कोविड–19 जैसी महामारी एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम व उपचार हेतु क्रिटिकल केयर को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज–अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर में 50–50 बेड क्षमता के नवीन ICU एवं 20–20 बेड क्षमता के NICU विकसित किये जायेंगे। इसी प्रकार, जिला चिकित्सालय भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर व सीकर में भी 30–30 बेड के ICU विकसित किये जायेंगे।
- कोविड महामारी के अनुभव को देखते हुए एक ही छत के नीचे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड इत्यादि बीमारियों की जांच, उपचार एवं रिसर्च के लिए जयपुर में **Institute of Tropical Medicine and Virology** की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, जयपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय स्तर के **Institute of Cardiology** की भी स्थापना की जायेगी।
- SMS Medical College, Jaipur में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हिपेटो पेनक्रियटो बिलेरी सर्जरी विभाग, गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरिनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग एवं यूरिनरी कैंसर रोगियों के लिए यूरोओंकोलॉजी डिविजन की स्थापना की जायेगी। इसी क्रम में, चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु SMS

Medical College, Jaipur में –

- अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) कार्यक्रम के अंतर्गत हार्ट लंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।
- श्वांस नली में रुकावट (Tracheal Stenosis) इत्यादि के उपचार के लिए ईएनटी विभाग में CO_2 लेजर मशीन स्थापित की जायेगी।
- ब्रेन स्ट्रोक रोगियों के बेहतर उपचार के लिए Neurovascular Angiography Lab की स्थापना PPP Mode पर की जायेगी।

- राज्य में बच्चों व गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं, उम्मेद अस्पताल परिसर, जोधपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय स्तर के **'Umaid Post Graduate Institute of Maternity and Neonatology** की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। साथ ही, पश्चिमी राजस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जोधपुर में **'Regional Cencer Institute** की स्थापना भी की जायेगी, जिसमें Radiotherapy, Surgical Oncology व Medical Oncology की सुविधायें विकसित करने हेतु 30 करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित है।
- राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में जीवन–रक्षक उपकरणों से युक्त 22 Advance Life Support (ALS) क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर तथा झालावाड़ में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से ट्रोमा सेन्टर विकसित किये जायेंगे।
- राज्य के 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालय चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किये जायेंगे।
- परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए हमने राज्य में पहली बार **राजस्थान आयुष नीति–2021** लागू की है। अब उसको मैं आगे बढ़ाते हुए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व सीकर में **आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी** के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही, उदयपुर व जोधपुर में **Yog and Naturopathy** के कॉलेज खोले जायेंगे। इन सभी कॉलेजों में पंचकर्म की सुविधायें भी विकसित की जायेंगी।

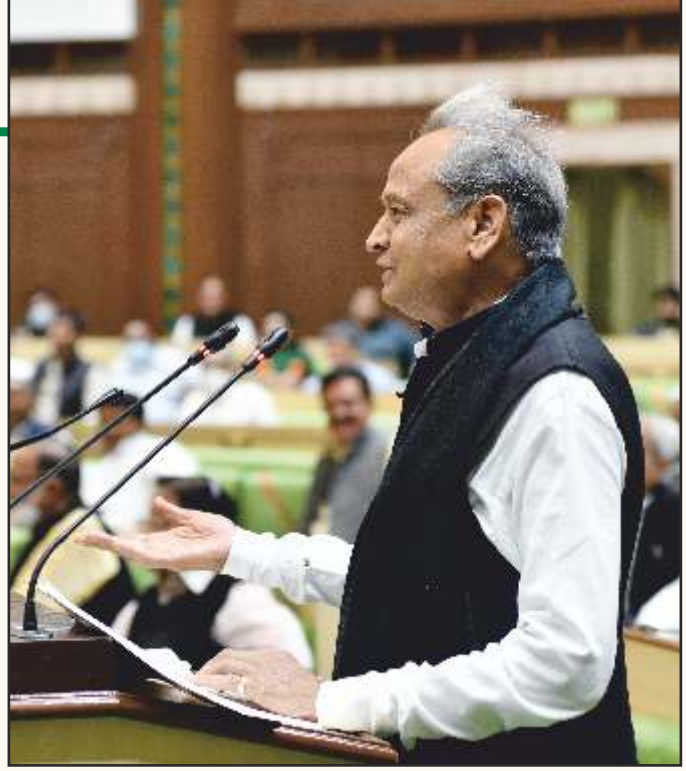

- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ **International Centre of Excellence in Panchkarm** बनाया जायेगा व विश्वविद्यालय रसायनशाला का विस्तार एवं Drug Testing Lab की स्थापना की जायेगी। इन पर कुल 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के Medi-Tourism Centres की PPP Mode पर चरणबद्ध रूप से स्थापना की जायेगी।
- विशेषज्ञ चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों में 8 विशिष्टिताओं में Post MBBS Diploma Courses प्रारंभ किये जायेंगे। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 400 अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
- प्रदेश में दूरस्थ स्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सों का अलग कैडर बनाया जायेगा। साथ ही, चिकित्सकों के अमूल्य समय का सदुपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों के लिए **Hospital Management Cadre** का गठन भी किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा **'शुद्ध के लिए युद्ध'** अभियान

चलाया गया था। आमजन की सेहत से खिलवाड़ न हो तथा यह अभियान होली–दिवाली तक ही सीमित ना रहे, इसके लिए अभियान की निरंतरता आवश्यक है। इस अभियान के सतत् एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **'Directorate of Food Safety'** बनाये जाने की घोषणा करता हूं।

- आगामी वर्ष में Silicosis Prevention and Research के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा। सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही, पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता राशि Auto Approval के माध्यम से Direct Transfer (DBT) की जायेगी।

सड़क सुरक्षा

- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 10 हजार से अधिक व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु होना चिंता का विषय है। इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके इसके लिए मैंने, पिछले बजट में तमिलनाडु की तर्ज पर एक रोडमैप तैयार करने की घोषणा की थी। उसी क्रम में–
  - **'जीवन रक्षक योजना'** (JRY) का गठन कर गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे।
  - घायल व्यक्ति का, बिना किसी पहचान एवं पात्रता के, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, प्रदेश के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क इलाज करना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - राज्य के राजमार्गों एवं मुख्य सड़कों पर Over Speed एवं Over Load वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए PPP Mode पर **Integrated Traffic Management System (ITMS)** विकसित किया जायेगा।
  - भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवायी जायेगी। इसके लिए नियम अधिसूचित कर इसको प्रभावी बनाया जायेगा।
  - वर्ष 2020–21 में 40 CHC को Primary Trauma Centre के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी क्रम में आगामी वर्ष में, 40 अन्य CHC को चिन्हित कर Primary Trauma Centre की सुविधा विकसित की जायेगी।

इन सबके लिए मैं, आगामी वर्ष **समर्पित सड़क सुरक्षा कोष** में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं।

- प्रदेश में सुमेरपुर–पाली, पोकरण–जैसलमेर व सादुलशहर–श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा–चित्तौड़गढ़, जैतारण–पाली व कुचामनसिटी–नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।

शिक्षा

- कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा का महत्त्व बढ़ गया है। इसलिए आगामी वर्ष में, समस्त राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 82 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।
- विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु Internet Connection Facility उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, Online Learning के लिए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में फ्री Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- **English Medium** के राजकीय विद्यालयों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, 5 हजार से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में **English Medium** के लगभग 1 हजार 200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। साथ ही, अभिनव पहल के रूप में जिला मुख्यालयों पर स्थित 33 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक (Pre-Primary) कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
- कृषि संकाय की मांग एवं विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि–वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन के विकल्प प्रदान करने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में **कृषि संकाय** खोले जायेंगे।

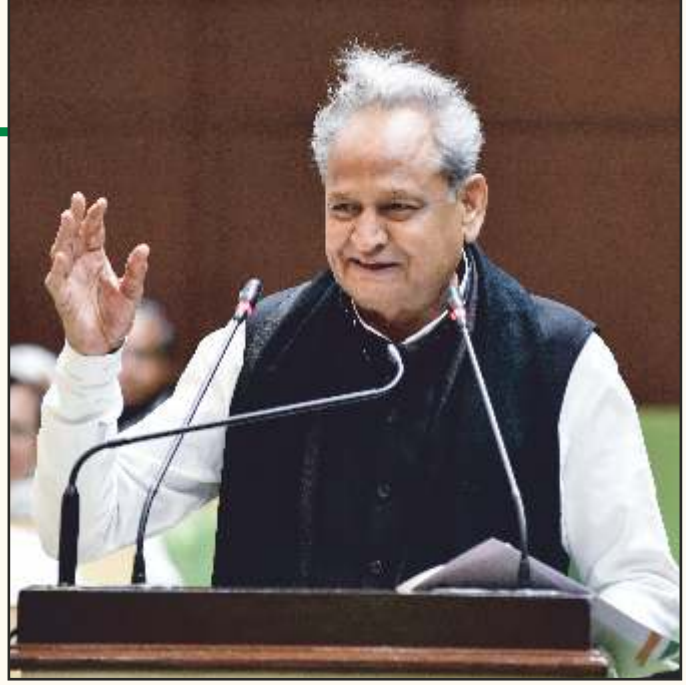

- राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से बुनियादी सुविधायें विकसित करने हेतु 3 हजार 500 से अधिक Class rooms, laboratiories, पुस्तकालय, आर्ट एवं क्राफ्ट, कम्प्यूटर रूम आदि का निर्माण, 15 नवीन भवनों का निर्माण एवं 70 विद्यालयों में वृहद् मरम्मत इत्यादि कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 450 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- स्थानीय विद्यालयों की देखरेख में संचालित 37 हजार 400 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा English Medium के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में Pre-Primary के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से Child Friendly Furniture उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 50 राजकीय विद्यालय खोले जायेंगे एवं 100 राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।
- जैसा कि आपको विदित है कि हमने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में **शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ (Peace and Non-Violence Cell)** का गठन किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के सिद्धान्त,आदर्श और दर्शन की पहले से ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए मैं, **शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ** को अपग्रेड कर **'शांति एवं अहिंसा निदेशालय'** के स्थापना की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत–
  - महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन–जन तक पहुंचाने तथा जन सामान्य में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से वर्तमान में संचालित 8 हजार 870 पुस्तकालयों को बढ़ाकर 14 हजार 970 किया जायेगा।
  - विद्यार्थियों में गांधीजी के विचारों एवं मूल्यों के प्रसार हेतु **सर्वोदय विचार परीक्षा** का आयोजन, इस कार्य को करने वाले NGO से समन्वय कर किया जायेगा। अब भविष्य में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति व अन्य Merit आधारित प्रोत्साहन हेतु छात्र–छात्राओं को यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- वर्ष 2019–20 में हमने **महात्मा गांधी संस्थान** तथा **गांधी दर्शन म्यूजियम** बनाये जाने की घोषणा की थी। इसकी प्रारंभिक तैयारी पूर्ण की जा चुकी है तथा शीघ्र ही इसका कार्य Central Park, Jaipur में स्थित राजकीय भूमि पर प्रारंभ किया जायेगा। इसकी कार्ययोजना को और वृहद् करते हुए इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इसी परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए Governance तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से TISS (Tata Institute of Social Sciences) व MIT (Maharashtra Institute of Technology-School of Governance, Pune) की तर्ज पर **महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज (Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Seiences-MGIGSS)** स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूं।
- वर्तमान में प्रदेश के 9 शैक्षिक संभागों में से 3 संभागों– बीकानेर, उदयपुर एवं जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2021–22 में शेष सभी शैक्षिक संभागों–कोटा, अजमेर, जोधपुर, पाली, चूरू एवं भरतपुर में विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूक–बधिरों को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए मैं, गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माता का थान–जोधपुर एवं पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु दो नवीन महाविद्यालय बनाने की घोषणा करता हूं।
- **राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर** को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया जाकर शिक्षा के क्षेत्र में Centre of Excellence के रूप में स्थापित किया जायेगा।

- तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं, जोधपुर में 400 करोड़ रुपये की लागत से **Fintech Digital University** स्थापित करने की घोषणा करता हूं। जिसमें School of Computer Science and IT, Finance and Accounting, Data Analytics व Analytical Mathematics की स्थापना की जायेगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के Collaboration से विभिन्न Latest Technology आधारित Courses उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से **Rajasthan Institute of Advanced Learning की Deemed University** के रूप में स्थापना की जायेगी।
- उच्च शिक्षा का व्यापक स्तर पर वातावरण तैयार किये जाने हेतु राज्य में **नवीन महाविद्यालयों** की स्थापना की जायेगी। इसके अंतर्गत–
  - पीपाड़–जोधपुर, फतेहगढ़–जैसलमेर, साहवा–चूरू, खण्डेला–सीकर, कुचेरा–नागौर, मण्डावर–दौसा, उदयपुरवाटी–झुंझुनूं, कल्याणपुर–बाड़मेर, मनियां (राजाखेड़ा)–धौलपुर व चिखली–डूंगरपुर में नवीन महाविद्यालय खोले जायेंगे।
  - रामगढ़ पचवारा (लालसोट)–दौसा, दूनी–टोंक, टोड़ाभीम, हिण्डौन सिटी–करौली, बाड़ी–धौलपुर, मेड़ता सिटी, लाडनूं–नागौर, तख्तगढ़–पाली, दांतारामगढ़–सीकर, नोहर–हनुमानगढ़, श्रीडूंगरगढ़–बीकानेर, सरदारशहर–चूरू, सूरसागर–जोधपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।
  - पिलानी–झुंझुनूं, मण्डोर–जोधपुर, उच्चैन–भरतपुर व नावां–नागौर में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- हम सभी को दु:ख है कि हमारे चार साथी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कुंवारिया–राजसमंद में किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीण्डर–उदयपुर में गजेन्द्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़–चूरू में मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय व गंगापुर–भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करता हूं।
- युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं कौशल विकास की दृष्टि से परबतसर–नागौर, समदड़ी (सिवाना)–बाड़मेर, बौंली (बामनवास)–सवाईमाधोपुर व भोपालगढ़–जोधपुर में आईटीआई खोले जायेंगे।
- निम्बार्क तीर्थ–अजमेर, सुल्तानिया, विमलपुरा (फागी), जोधराला (जमवारामगढ़)–जयपुर, पावटा (महुवा)–दौसा, टोड़ाभीम–करौली, दलोट–प्रतापगढ़ व शिवाजी नगर (किशनगढ़)–अजमेर के संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा। संस्कृत विद्यालय सैदपुरा (नदबई)–भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जायेगा। साथ ही, बांसवाड़ा में 25 करोड़ रुपये की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना प्रस्तावित है।
- विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए राज्य में 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर Incubation Cell स्थापित किये जायेंगे। इस प्रकार **School Startup** कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए इन Startups को Hub & Spoke Model के माध्यम से Techno Hub से जोड़ा जायेगा।
- प्रदेश में युवाओं को नवीनतम IT जैसे Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics एवं Virtual Reality में Certificate Courses व Multi Discipilinary Research कराने के साथ–साथ आमजन को आकर्षक रूप से इन तकनीकों की जानकारी कराने के लिए मैं, जयपुर में लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि से **Rajiv Gandhi Centre of Advance Technology (RCAT)** स्थापित करने की घोषणा करता हूं।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को Guest Faculty के रूप में लेने के लिए **विद्या संबल योजना** लागू की जायेगी।

- प्रदेश के लगभग 1 हजार 500 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए Science & Space Club खोले जायेंगे। इनमें NASA (National Aeronautics and Space Administration, USA) के सहयोग से Asteroid खोज अभियान भी चलाया जायेगा।

युवा एवं रोजगार

- जैसा कि हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न **राजीव गांधी जी** ने देश को 21st Century में अग्रणी बनाने के लिए कहा है कि–

'India is an old country but a young nation...
I am young and I too have a dream,
I dream of India Strong, independent, self-reliant and in the front rank of the nations of the world, in the service of mankind.'
'भारत एक प्राचीन देश, लेकिन एक युवा राष्ट्र है...
मैं युवा हूं और मेरा भी एक सपना है,
मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर
और दुनिया के सभी देशों में अग्रणी लाना
और मानव जाति की सेवा करना।'

- हम चाहते हैं कि राज्य के युवा राजीव गांधी जी के इन आदर्शों से प्रेरणा लें और सशक्त एवं कुशल बनकर राज्य की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दें व प्रदेश के विकास में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारी सरकार हर वक्त, हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी।
- मैं, इस अवसर पर युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति **डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम** की ये पंक्तियां याद दिला चाहूंगा–

'सपने वो नहीं हैं, जो आप नींद में देखें,
सपने वो हैं, जो आपकी नींद ही उड़ा दें।'

- **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना–2019** को बेहतर बनाते हुए, Employable बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवायी जायेगी एवं पात्र युवाओं को वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते को **एक हजार रुपये** बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में 650 करोड़ रुपये व्यय कर हमने 1 लाख 60 हजार युवाओं को लाभान्वित किया था, अब इस योजना से लगभग 2 लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे।
- आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में **राजीव गांधी युवा कोर (RYC)** का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 2 हजार 500 **'राजीव गांधी युवा मित्रों'** का चयन किया जायेगा। साथ ही, राज्य के समस्त गांवों में लगभग 50 हजार महिला एवं पुरुष **राजीव गांधी युवा Volunteers** भी बनाये जायेंगे।
- सरकार में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से, एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर **समान पात्रता परीक्षा Common Eligibility Test** लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, अभ्यर्थियों को बार–बार दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं पुलिस वेरिफिकेशन से छुटकारा दिलाने के लिए One time Verification system बनाया जायेगा।
- मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी। साथ ही, प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को भी यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में **50 हजार** से अधिक पदों पर भर्तियां की जायेंगी।

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल पद
1	Agriculture	1674
2	Animal Husbandry	836
3	Ayurveda	890
4	Education	19000
5	Forest	1700
6	Home	8438
7	Medical Education	336
8	Medical Health	5000
9	PHED	3838
10	PWD	1538
11	Revenue	1100
12	Other Departments	8000

- प्रदेश के युवाओं एवं बच्चों के शारीरिक विकास हेतु गत वर्षों में हमने खेलकूद प्रतियोगिताएं कराने के साथ–साथ खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए–
  - मैं, **मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना** शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किये जायेंगे। इसके लिए विधायक–सांसद निधि/जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
  - मोरोली–भरतपुर में खेल स्टेडियम एवं काछवा–सीकर में भी खेल सुविधायें विकसित की जायेंगी।
  - अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपरपज इंडोर हॉल तैयार करवाये जायेंगे।
  - राजसमन्द, सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम एवं प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा।
- प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए लोकप्रिय खेलों जैसे–कबड्डी, वॉलीबाल, क्रिकेट (टेनिस बॉल) एवं हॉकी के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय Tournamernts कराये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- SMS स्टेडियम, जयपुर व अमृतलाल गहलोत स्टेडियम, चैनपुरा स्कूल मण्डोर, जोधपुर में **Residential Sports School** बनाये जायेंगे। जिसमें खिलाड़ियों को आवास, शिक्षा व खेल प्रशिक्षण की सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध होंगी। खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी आधारित फिजियोथैरेपी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से SMS स्टेडियम, जयपुर में **High Performance Training and Rehabilitation Centre** की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- पश्चिमी राजस्थान की मांग को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच एवं आईपीएल टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए **बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम, जोधपुर** के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य 20 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाये जायेंगे।
- प्रदेश में डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी प्रारंभ की जायेगी।
- राज्य में युवाओं को अच्छी सुविधा देने हेतु यूथ हॉस्टल उदयपुर, जोधपुर, अजमेर की साज–सज्जा व सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जायेंगे। साथ ही यूथ हॉस्टल, जयपुर को **'यूथ एक्सीलेंस सेंटर'** के रूप में विकसित किया जायेगा। इन पर 5 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

कृषक एवं पशुपालक कल्याण

- **गांधीजी** ने कहा था कि, **'अगर भारत को शांतिपूर्ण सच्ची प्रगति करनी है तो पैसे वाले यह समझ लें कि किसानों में ही भारत की आत्मा बसती है।'** हमारी सरकार भी हमेशा से किसान हितैषी रही है और कृषि ऋण माफी समेत कई महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजनायें लाती रही है। केन्द्र के तीन विवादित कृषि कानूनों के स्थान पर, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने तीन विधेयक गत विधानसभा सत्र में पारित कराकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को अग्रेषित किये हैं। हमें विश्वास है कि इन विधेयकों को राष्ट्रपति महोदय को शीघ्र प्रेषित किया जायेगा। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए, अन्नदाता के बेहतर भविष्य एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए आगामी वर्ष से **'कृषि बजट'** की शुरुआत करना प्रस्तावित करता हूं।
- अपने वादे को निभाते हुए हमारी सरकार ने 20 लाख 89 हजार किसानों के 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ किये है। साथ ही, हमने गत सरकार के समय से लंबित 6 हजार करोड़ रुपये का भी भुगतान किया और कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि के किसानों के ऋण माफ किये।
- हमने अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी का लाभ देने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इस संबंध में भारत सरकार से अभी तक सहमति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में भी हम State Level Bankers Committee (SLBC) के सम्पर्क में रहकर प्रयासरत हैं कि ऋण माफी से शेष रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी कृषकों के ऋण, बैंकों की One Time Settlement योजनाओं का उपयोग करते हुए माफ करवाया जाये।

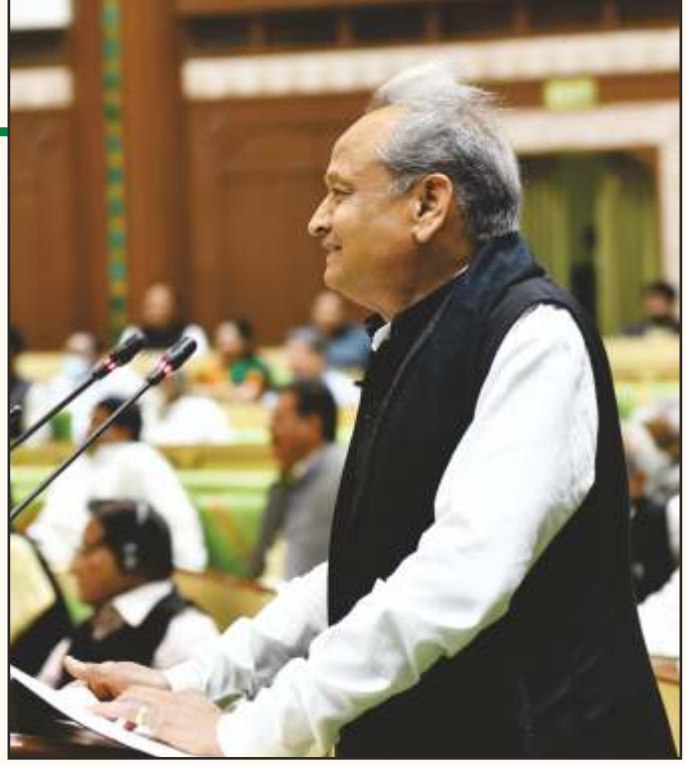

- हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में **ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना** लागू की गई थी। वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के बावजूद भी हम 87 प्रतिशत ऋण वितरण के लक्ष्यों को पूर्ण कर पाये। आगामी वर्ष में, प्रदेश के किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जायेंगे। साथ ही, इस योजना में वर्ष 2021-22 में **3 लाख नये किसानों** को जोड़ते हुए मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को सम्मिलित करना प्रस्तावित है।
- कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मैं **कृषक कल्याण कोष** के माध्यम से आगामी तीन वर्ष हेतु अनुदान आधारित **'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना'** लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत-
  - 3 लाख कृषकों को नि:शुल्क Bio Fertilizers एवं Bio Agents दिये जायेंगे।
  - एक लाख कृषकों के लिए कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की जायेगी।
  - तीन लाख कृषकों को **'micro nutrients kit'** उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किये जायेंगे।
  - 30 हजार कृषकों के लिए डिग्गी व फार्म पॉण्ड बनाये जायेंगे।
  - 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिये जायेंगे।
  - 120 Farmer Producer Organisation (FPO) का गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, जिसके अंतर्गत उत्पादों की cleaning, grinding एवं Processing इकाइयां स्थापित की जायेंगी, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
  - इन सब कार्यों पर 2 हजार करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- प्रदेश में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता को देखते हुए आगामी तीन वर्षों में लगभग 4 लाख 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जायेगा। साथ ही, फर्टिगेशन एवं ऑटोमेशन आदि तकनीकों को भी व्यापक प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए 732 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- मैं, कृषि जिंसों एवं उनके processed उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से **मिनी फूड पार्क** स्थापित करने की घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष में पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर, करौली, बीकानेर एवं दौसा जिलों में 200 करोड़ रुपये की लागत से मिनी फूड पार्क बनाये जायेंगे। साथ ही, मथानिया-जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से **मेगा फूड पार्क** की स्थापना की जायेगी।
- किसानों को उनकी उपज के विपणन व बेहतर मूल्य दिलाये जाने के लिए आगंणवा-जोधपुर में आधुनिक सुविधा युक्त **ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी** स्थापित की जायेगी। इस पर 60 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवायें देने के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में 125 करोड़ रुपये की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में एक हजार **किसान सेवा केन्द्रों** का निर्माण करवाया जायेगा। इसके लिए कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नये पद भी सृजित किये जायेंगे।
- हमने सरकार बनाते ही 5 वर्षों हेतु किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी। किसानों को इस वर्ष हम 12 हजार 700 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं तथा आगामी वर्ष के लिए भी 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का

प्रावधान प्रस्तावित है। खेती हेतु पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, बिजली खरीद में पारदर्शिता व अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए मैं, नयी **कृषि विद्युत वितरण कम्पनी** बनाने की घोषणा करता हूं।

- ऊर्जा विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष DBT करने का पूर्व में प्रावधान किया गया था। वर्तमान में उक्त राशि देय नहीं है। अब मैं, पूर्व में संचालित योजना को और अधिक बेहतर बनाते हुए उड़ीसा सरकार की स्कीम की तर्ज पर, ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है, को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपये तक की राशि दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 1 हजार 450 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय संभावित है।
- बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ता (150 यूनिट तक) एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल प्रत्येक माह के स्थान पर अब दो माह में भेजे जायेंगे।
- किसान साथियों को निरंतर बिजली मिल सके, इसके लिए मैं, 50 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने तथा अन्य 50 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा, कटे हुए कृषि कनेक्शनों को पुनर्जीवित करने की वर्तमान अवधि 15 वर्ष को बढ़ाकर 20 वर्ष किया जायेगा।
- राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में संपर्क सड़क निर्माण, अन्य आधारभूत संरचना विकसित करने तथा मंडियों को ऑनलाइन करने हेतु आगामी तीन वर्षों में **एक हजार करोड़** रुपये की लागत के कार्य कराये जायेंगे।
- परबतसर, लाडनूं–नागौर, उच्चैन–भरतपुर, फतेहगढ़ व सुथारमण्डी–जैसलमेर में कृषि उपज मंडी, पूगल (खाजूवाला)–बीकानेर में गौण मण्डी बनाया जाना तथा दूदू–जयपुर को स्वतंत्र मण्डी व तारानगर–चूरू को मुख्य मण्डी घोषित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, पादरू (सिवाना)–बाड़मेर में फल–सब्जी मण्डी बनायी जायेगी।
- जोधपुर संभाग के किसानों को एक ही स्थान पर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पावटा स्थित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यालयों को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी (अनाज), भदवासिया–जोधपुर में स्थानांतरित कर **किसान कॉम्पलेक्स** बनाया जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- प्रदेश में खेती की लागत को कम करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने वर्ष 2019 में Zero Budget Natural Farming योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 60 करोड़ रुपये व्यय कर 15 जिलों के 36 हजार किसानों को लाभांवित किया जायेगा।
- बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तथा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बस्सी–जयपुर में डेयरी व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। साथ ही, डूंगरपुर, हिण्डौली–बूंदी एवं हनुमानगढ़ में नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- दूध उत्पादन को बढ़ावा देने व उत्पादकों की सहूलियत के लिए मैं, राजसमंद जिले में स्वतंत्र रूप से नये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के गठन की घोषणा करता हूं। वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में नये दुग्ध संकलन रूट प्रारंभ करने के साथ ही जिला दुग्ध संघों में संचालित 1 हजार 500 दुग्ध संकलन केन्द्रों को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
- कृषि कार्य में समय की बचत तथा खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त कृषकों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने हेतु मैं, चरणबद्ध रूप से PPP Mode पर GSS एवं अन्य जगहों पर एक हजार **कस्टम हायरिंग केन्द्रों** की स्थापना करना प्रस्तावित करता हूं। इस पर 20 करोड़ रुपये की लागत संभावित है।
- वर्ष 2021–22 में 100 पैक्स/लैम्प्स में प्रत्येक में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करवाया जायेगा। इस पर 12 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- मैं, प्रदेश की गोशालाओं व पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर **'102–मोबाइल वेटेनरी सेवा'** शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस पर आगामी वर्ष में 48 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
  - प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु
  - जोबनेर में पशु विज्ञान केन्द्र व नावां–नागौर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।

- वर्तमान में संचालित 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों व 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजकीय पशु चिकित्सालय बोराडा (किशनगढ़)–अजमेर को राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- पीलवा (डीडवाना)–नागौर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जायेगा।

- पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सालय में **राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी** का गठन किया जायेगा।
- पूर्व में सभी गोशालाओं के विद्युत कनेक्शन के लिए अघरेलू दर लागू थी। फरवरी, 2020 से पंजीकृत गोशालाओं के लिए घरेलू दर लागू की गयी है। गोशालाओं को आर्थिक संबल देते हुए, आगामी वर्ष से सभी पंजीकृत गोशालाओं के लिए घरेलू दर की आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
- हमने प्रत्येक ब्लॉक में नंदी शाला बनाने की घोषणा की थी। इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नंदी शालाओं को 1 करोड़ 50 लाख रुपये के मॉडल के आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष 111 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।
- प्रदेश के प्रगतिशील किसानों (Progressive Farmers) की तरह ही, प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष **राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह** आयोजित किये जायेंगे।

उद्योग

- MSME उद्योगों के विकास तथा उद्यमियों व निवेशकों के लिए Investment friendly वातावरण तैयार करने व रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा MSME Act 2019 लाया गया।
- राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए नई नीति जारी किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत गुणवत्ता नियंत्रण सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग लेबोरेट्री स्थापना, महिला SC-ST उद्यमियों के स्किल अपग्रेडेशन, निर्यात प्रोत्साहन, ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म आदि संबंधी समुचित प्रावधान किये जायेंगे।
- राज्य में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) से वंचित 147 उपखण्डों में से वर्ष 2021–22 में प्रथम चरण में **64 उपखण्डों** में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
1	अलवर	बानसूर, रामगढ़, मालाखेड़ा, रैणी
2	बांसवाड़ा	बागीदोरा, आनन्दपुरी, छोटी सरवन
3	बांरा	मांगरोल, किशनगंज, अटरू
4	बाड़मेर	गडरारोड (शिव), बायतू, चौहटन, धोरीमन्ना
5	भरतपुर	भुसावर, रूपवास, नगर
6	भीलवाड़ा	माण्डल
7	बूंदी	केशोरायपाटन, नैनवां, हिण्डोली
8	चित्तौड़गढ़	बेगूं
9	चूरू	राजगढ़
10	दौसा	सिकराय, नांगल राजावतान (लालसोट)
11	धौलपुर	राजाखेड़ा, बसेड़ी, सरमथुरा
12	डूंगरपुर	सिमलवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट
13	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर
14	जयपुर	जमवारामगढ़, विराटनगर
15	जालोर	चितलवाना
16	जैसलमेर	पोकरण
17	झुंझुनूं	खेतड़ी, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, मलसीसर
18	जोधपुर	भोपालगढ़, लोहावट, बावड़ी
19	करौली	मण्डरायल, सपोटरा, टोड़ाभीम
20	कोटा	दीगोद, सांगोद
21	नागौर	जायल, नावां, लाडनूं
22	प्रतापगढ़	अरनोद
23	राजसमंद	नाथद्वारा, रेलमगरा
24	सवाई माधोपुर	खण्डार, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, मलारनाडूंगर, बामनवास
25	सीकर	लक्ष्मणगढ़, धोद
26	टोंक	पीपलू, टोडारायसिंह
27	उदयपुर	खैरवाड़ा

- अलवर में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, टपूकड़ा व आसपास के नये क्षेत्र शामिल कर मैं, नयी एवं उन्नत **Greater Bhiwadi Industrial Township** बनाने की घोषणा करता हूं। यह टाउनशिप राजस्थान के औद्योगिक परिवेश में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रथम चरण में **एक हजार करोड़ रुपये** का निवेश किया जायेगा।
- इसके साथ ही, जोधपुर–कांकाणी–रोहट–पाली–मारवाड़ क्षेत्र में **Marwar Industrial Cluster** बनाने की भी घोषणा करता हूं। जिससे मारवाड़ क्षेत्र को Dedicated Freight Corridor के तहत आने वाले DMIC के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर **750 करोड़ रूपये** व्यय किये जायेंगे। रीको को इसके लिए Regional Development Authority बनाया गया है।
- नये निवेशकों को आकर्षित करने एवं निवेश संबंधी कार्य on the spot करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में देश–विदेश में Road Shows करने के साथ–साथ, राजस्थान फाउण्डेशन के सहयोग से जयपुर में **Rajasthan Investors Summit** का आयोजन किया जायेगा।
- राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट व IT Professionals अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर को देश में **Fintech City** के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मैं, **Fintech Park (Financial Technology Park)** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।
- जोधपुर, फार्मा एवं स्वास्थ्य उपकरणों के हब के रूप में उभर रहा है। इसको देखते हुए जोधपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से एक **Biotech Pharma Business Incubation & Research Centre** स्थापित किया जायेगा।
- Ease of Doing Business को प्राथमिकता देते हुए Inspection राज खत्म करने की दृष्टि से विभिन्न विभागों में अनावश्यक Inspections की प्रथा समाप्त कर Computerised Risk Based Analysis के आधार पर Random Roster से अधिकारियों का चयन कर ही Inspections करने की प्रक्रिया लागू करना प्रस्तावित है।
- वर्तमान में Handloom क्षेत्र में कार्डधारक बुनकरों को एक लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज का शत–प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब Handicraft क्षेत्र के दस्तकारों के लिए भी 3 लाख रुपये तक के ऋण पर शत–प्रतिशत ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
- उद्योग विभाग द्वारा वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर एवं लघु उद्योगों के वर्ष 2000 तक के विभिन्न योजनाओं में बकाया समस्त ऋणों को माफ किया जायेगा। इससे लगभग 3 हजार उद्यमी लाभान्वित होंगे।
- प्रदेश के दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दिल्ली हाट की तर्ज पर **जयपुर हाट** विकसित किया जायेगा एवं आधुनिक म्यूजियम की भी स्थापना की जायेगी। साथ ही, सीकर के अपूर्ण रहे अर्बन हाट को आगामी वर्ष में पूर्ण कराने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- प्रदेश के विकास में युवाओं को आगे लाने व उनकी उद्यमिता का विकास करने की दृष्टि से हम प्रदेश में **Startups** को विभिन्न सुविधायें दे रहे हैं। वर्तमान में i-Start कार्यक्रम बड़े शहरों तक सीमित है। राज्य का ग्रामीण युवा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ–साथ Innovation करने की क्षमता को भी समय–समय पर प्रदर्शित कर चुका है। अत: आगामी वर्ष में **Rural i-Start** कार्यक्रम वृहद् स्तर पर लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- युवाओं को प्रतिभा दिखाने व स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप्स को बढ़ावा जायेगा। राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को, विभिन्न विभागों द्वारा, चयनित कार्यों हेतु 15 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिये जा सकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा

- अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के उन सभी तबको की सेवा के लिए तत्पर है जिन्हें आज भी समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम महिलाओं, विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। माननीय सदन को **मदर टेरेसा** की पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगा–

'हम में से सभी महान काम नहीं कर सकते हैं,

लेकिन हम छोटी चीजें अधिक प्रेम से कर सकते हैं।'

'Not all of us can do great things,
But we can do small things with great love.'

- प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं, विशेष **'राजस्थान पैटर्न'** लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled tribe Development कानून बनाया जायेगा।
- विभिन्न Professional Courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC व EWS के छात्र–छात्राओं हेतु **'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'** लागू करने की मैं, घोषणा करता हूं। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में Academic Courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु Professional Coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5–5 हजार छात्र–छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में SC, ST, OBC, MBC व EWS वर्ग की कॉलेज छात्राओं के लिए छात्रावास चलाये जा रहे हैं। अब इन वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु **अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना** लागू करना प्रस्तावित करता हूं। इसके तहत पांच हजार छात्र लाभान्वित होंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया–उदयपुर, धरियावाद, अरनोद–प्रतापगढ़, सागवाड़ा–डूंगरपुर, गढ़ी–बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे।
- बारां जिले के सहरिया क्षेत्र–खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सांगानेर–जयपुर, मुण्डावर, नारायणपुर (थानागाजी)–अलवर, डीग–भरतपुर, पाटन–सीकर, सज्जनगढ़–बांसवाड़ा व बीकानेर स्थित 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। इस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।
  - राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अध्ययन की

सुविधा हेतु–
  - 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण ब्लॉक लक्ष्मणगढ़–अलवर, ब्लॉक रायसिंहनगर व अनूपगढ़–श्रीगंगानगर, ब्लॉक मसूदा–अजमेर, फतेहपुर–सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं टोंक में करवाया जायेगा।
  - भणियाना ब्लॉक साकड़ा–जैसलमेर, ब्लॉक रामगढ़–अलवर एवं उदयपुर में 3 राजकीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी, जिस पर 62 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
  - सीकर, चौहटन–बाड़मेर व पहाड़ी (कामां)–भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।
  - जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जायेंगे।
- राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु बाड़मेर में तीन तथा अलवर व भरतपुर जिले में एक–एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही, अलवर में 10, अजमेर में 5 तथा जैसलमेर में 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
- SC, ST, OBC व Minority के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपये के **विकास कोष** का गठन किया जायेगा। साथ ही, Transgenders के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि से **उत्थान कोष** बनाया जायेगा।
- देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का पैकेज

दिया जा रहा है। साथ ही, आगामी वर्ष में MBC के लिए 3 छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।

- प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय यथा गाड़िया लुहार, बंजारा, सांसी, बावरी भाट, नट तथा मदारी, सपेरा, बहरूपिये इत्यादि के उत्थान हेतु DeNotified Tribes (DNT) Policy लायी जायेगी, जिसके अंतर्गत–
  - DNTs के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना की जायेगी।
  - इनके पारम्परिक कला एवं उद्यम हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि से DNT Research and Preservation Centre बनाया जायेगा।
- जामड़ोली–जयपुर स्थित संस्थान में वृद्धजनों को रखने की क्षमता को 25 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, राजकीय वृद्धाश्रम पुष्कर, अजमेर की क्षमता 25 वृद्धजन से बढ़ाकर 50 की जायेगी।
- राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन, जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बीपीएल के समकक्ष माना जायेगा।
- कक्षा 1 से 4 तक तथा कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली वर्तमान छात्रवृत्ति को क्रमशः 40 से बढ़ाकर 500 रुपये एवं 50 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूं।
- कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र–छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए युवाओं को दो हजार Scooty दी जायेंगी। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।
- राज्य में अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, दृष्टिबाधित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों व छात्रावासों में कार्यरत मानदेयकर्मियों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को दुगुना किये जाने की घोषणा करता हूं।
- बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने तथा उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए **नेहरू बाल संरक्षण कोष** के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालय पर **समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों** की स्थापना, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए अभिनव पहल करते हुए NGOs व Civil Society से समन्वय कर, सभी जिला मुख्यालयों पर **गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर** का संचालन प्रस्तावित करता हूं।
- आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने व प्री–स्कूल गतिविधियों की समुचित व्यवस्था करने के लिए मैं, 25 हजार आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध रूप से नन्द घर योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित करता हूं।
- Health एवं Hygiene को ध्यान में रखते हुए छात्राओं एवं किशोरियों को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी महिलाओं को आवश्यकतानुसार यह सुविधा **'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना'** के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां घूंघट प्रथा भी है तथा महिलायें अपनी ऐसी समस्याएं किसी से संकोचवश कह नहीं पाती हैं व इस कारण अनेक रोगों से ग्रसित हो जाती हैं तथा उन्हें समय पर इलाज भी नसीब नहीं होता। अतः महिला SHG सामाजिक संस्थाओं एवं NGOs के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाकर सेनेटरी नेपकिन का वितरण करवाया जायेगा। इस हेतु इन संगठनों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने एवं काउंसलिंग के लिए जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर **इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों** की स्थापना प्रस्तावित करता हूं। इन पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाये जाने के लिए, राजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री की एक लाख रूपये तक की सीधी सरकारी खरीद का प्रावधान, अमृता सोसायटी की तर्ज पर किया जायेगा।
- जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 मां–बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- जनजाति उपयोजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45 हजार

जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संग्रहित लघु वन उपजों का Value addition कर, मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 **वनधन केन्द्रों** का गठन किया जायेगा। इस पर लगभग 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

- शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए मैंने वर्ष 2013 में **लीलूडी बडली शहीद स्मारक** का गांव भूला–सिरोही में शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए अब इस स्मारक को पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं।
- शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता–पिता को वर्तमान में देय सम्मान भत्ता 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। साथ ही, शहीद सैनिकों के आश्रित माता–पिता के भरण–पोषण के लिए वर्तमान 3 लाख की FD (Fixed Deposit) को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार प्रतिमाह की जायेगी।
- देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों एवं आत्मनिर्भर मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय क्रमश: 1 हजार 800 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार एवं 3 हजार 600 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह किया जायेगा।

आधारभूत संरचना :

- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ–साथ आमजन को अन्य बुनियादी सुविधायें जैसे– बिजली, पानी, सड़क, आवास आदि उपलब्ध कराना हमारी सरकार की हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के दौरान ज्यादातर समय में कोविड की वजह से लॉकडाउन की स्थिति रही। इस वजह से कई कार्य देरी से प्रारंभ हुए या अपूर्ण रहे हैं। अत: हमारी मंशा है कि आगामी वर्ष में इन सुविधाओं का काम तीव्र गति से करते हुए विस्तार किया जाये।

सड़क–शहरी विकास :

- मैं, प्रदेश में सड़कों के सुनियोजित विकास के लिए वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि हेतु **नवीन राज्य सड़क नीति–2021** लाया जाना प्रस्तावित करता हूं।

- माननीय सदस्यों के माध्यम से सड़कों के Repair Strengthening, Upgradation एवं निर्माण से संबंधित प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अत: इसको ध्यान में रखते हुए–
  - आगामी वर्ष में एक हजार करोड़ रुपये की राशि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये लागत के नॉन–पेचेबल या मिसिंग लिंक सड़क के कार्य कराने तथा
  - राज्य के सभी जिलों में 7 हजार 257 किलोमीटर लम्बाई की अन्य जिला सड़कों (ODR) व ग्रामीण सड़कों को राज्य राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों (MDR) में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।
- आधारभूत संरचना में सड़कों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग 1 हजार 900 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे–

जिला	सड़क का नाम (पंचायत समिति का नाम)
अलवर	अलवर–जयपुर सड़क से सिलीसेड़–घरभाजी सड़क (उमरेण)
	SH-52 ज्ञानपुरा सीकर सीमा तक वाया कराना–राजनोता–रघुनाथपुरा (बानसूर)
	किशनगढ़–कोटकासिम–बोलनी राज्य सीमा तक (किशनगढ़बास)
अजमेर	केकड़ी शहर की सड़क का 2 लेन से 4 लेन में चौड़ाईकरण (केकड़ी)
	NH-79 झिपिया वाया राताकोट (मसूदा)
	नये बस स्टेण्ड किशनगढ़ से फरासीया फाटक

	(किशनगढ़)
बांसवाड़ा	तेजपुर से बोरवट सड़क Urban Link through बांसवाड़ा सड़क मय पुलिया (बांसवाड़ा)
	संपर्क सड़क मुवाल से महुड़ाफला पाड़ला सड़क पर पुल निर्माण कार्य (कुशलगढ़)
	सपंर्क सड़क पोटलिया पर पुल निर्माण कार्य (कुशलगढ़)
बारां	अन्ता–सीसवाली हाई लेवल ब्रिज (अंता)
	मेरमाचाह से चौकी बोरदा मय पुलिया निर्माण (अटरू)
	किशनगंज से मांगरोल वाया रामगढ़ सड़क पर हाई लेवल ब्रिज (किशनगंज)
बाड़मेर	भाड़खा–बाटाडू–कानोड़–गिड़ा–परेऊ–पाटोदी (बायतु)
	उतरलाई जिप्सम हॉल्ट जालिपा–हरसाणी (बाड़मेर ग्रामीण)
	संपर्क सड़क बाड़मेर–गडरारोड़ से बाड़मेर चौहटन (रामसर, चौहटन)
भरतपुर	पान्हौरी से नदबई वाया जनूथर ऐचेरा (नगर,नदबई)
	बाड़ी–बसेड़ी–बंध–बारैठा–उच्चैन भरतपुर सौंख (बयाना, उच्चैन)
	सेंथरा से इकरन मोड़ वाया जाटौलीरथभान पीपला इकरन (सेवर)
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा से देवगढ़ वाया पान्सल–पिथास–बागौर–रायपुर–बोराना–जगदीश सड़क जिला सीमा तक (सहाड़ा)
	भीण्डर–रामगढ़ वाया फतहनगर–गंगापुर–रायपुर–करेड़ा (आसींद)
	मानपुरा–जलीन्द्री सड़क मय पुलिया निर्माण (मांडलगढ़)
बीकानेर	NH-11 उरमुल सर्किल–करमीसर रोड़ जंक्शन व NH-89 गोगागेट सर्किल–उदयरामसर जंक्शन (बीकानेर)
	बीकानेर–झझु–दासुडी रोड (कोलायात)
	बछासर से चावला बस्ती से NH-11 (खाजूवाला)
बूंदी	धनावा–धाबाइयों का नयागांव–दबलाना–रानीपुरा–बांसी–दुगारी–नैनवां मय उच्च स्तरीय पुल (हिण्डौली)
	बूंदी–दलेलपुरा–अलोद–मेण्डी MDR-52 सड़क (बूंदी, हिण्डौली)
	पैच की बावड़ी से थाना रोड़ जिला सीमा तक (हिण्डोली)
चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा से अरनिया माली सेगवा सड़क (निम्बाहेड़ा)
	रावतभाटा–जवाहर नगर (बेगूं)
	पांडोली–झातला माता–नेतवाल महाराज–छापरी सड़क (चित्तौड़गढ़ कपासन)
चूरू	भालेरी–कोहिणा–साहवा (तारानगर)
	सीकर नोखा सड़क, लेफ्ट आउट पोर्शन (सुजानगढ़)
	एलसी संख्या–21 पर सुजानगढ़ पर आरओबी निर्माण कार्य (सुजानगढ़)
दौसा	NH-21 से NH-148 वाया छतरीवाली ढाणी–सीर्रा की ढाणी–दुर्गा मंदिर–मालपुरा–चादराना जिला सीमा तक (दौसा)
	NH-148 से मौरोली वाया पीपली–पातलवास–कोलीवाड़ा–डोब–पपलाज माता–सरधोण (लालसोट)
	गोल्या मोड़ NH-25 से टोरडा वाया गांगदवाड़ी–गण्डरावा–टोरड़ा रोड (सिकराय)
धौलपुर	बाड़ी रोड़ से भरतपुर धौलपुर रोड को जोड़ते हुए सैंपऊ में बाईपास (सैंपऊ)
	बाड़ी शहर में रिंग रोड का निर्माण (बाड़ी)
	बसेड़ी–जगनेर रोड़ (बसेड़ी)
डूंगरपुर	डचकी से लिमडिया फला मय पुल (डूंगरपुर)
	सांगवाड़ा–कोकापुर–पादरा–पुनाली सड़क (सागवाड़ा–दौबड़ा–आसपुर)
	आसपुर–डूंगरपुर–सरथुना सड़क (डूंगरपुर–आसपुर–दौबड़ा)
हनुमानगढ़	हनुमानगढ़–अबोहर सड़क (SH-7A) (हनुमानगढ़)
	हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर सड़क (SH-36) पर श्रीगंगानगर–हनुमानगढ़ रेलवे सेक्शन के किमी 201/0–1 पर रेलवे फाटक संख्या 176 के स्थान पर आरओबी निर्माण कार्य (हनुमानगढ़)
	नोहर–सरदारशहर सड़क (नोहर)
जयपुर	झोटवाड़ा–खोराबीसल–नांगल लाड़ी–पुनाना–भैंसावा (झोटवाड़ा–आमेर)
	फागी से मोहनपुरा–राजावतान वाया किशोरपुरा–सेमलिया (फागी)
	खेजरोली मूंडरू सड़क से सिमारड़ा वाया ऊंटगढ़ा (गोविंदगढ़)
जैसलमेर	गडरा रोड से नाचना वाया चावा–बायतु–काणोद (भणियाना, साकड़ा)
	जैसलमेर झिनझिनयाली (जैसलमेर, फतेहगढ़)
	पोकरण से झिनझिनयाली वाया सांकड़ा भैंसड़ा डांगरी फतेहगढ़ (साकड़ा–फतेहगढ़)

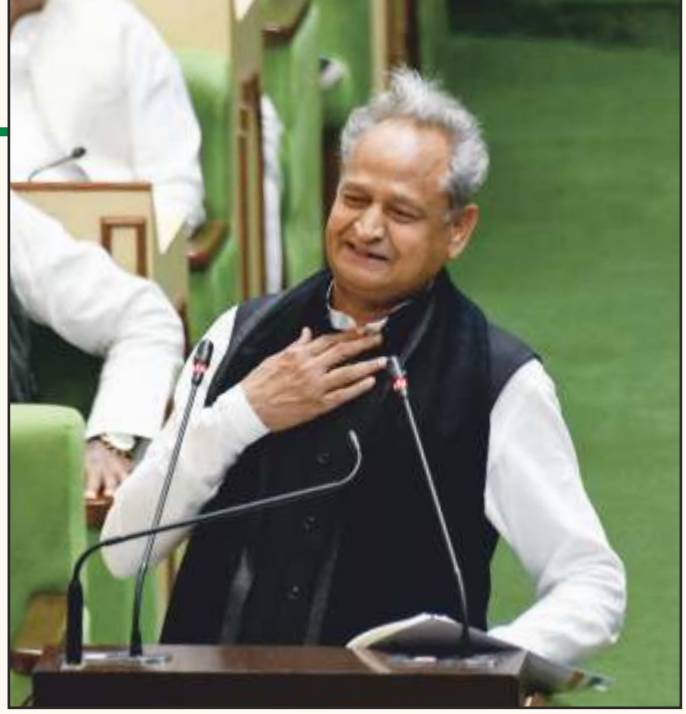

जालोर	गोदन–बिशनगढ़ सड़क (जालोर)
	सांचौर–रानीवाड़ा–मण्डार सड़क (रानीवाड़ा)
	जानवी–खासरवी–सुथड़ी–सुराचन्द (चितलवाना)
झालावाड़	नलखेड़ी–आकखेड़ी–गुराडिया माना प्रदेश सीमा तक (भवानीमंडी)
	परवन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कलमोदिया हरनावदा मनोहरथाना राजगढ़ सड़क खाताखेड़ी गांव के पास (मनोहरथाना)
	रतलाई–करालगांव–बकानी सड़क (बकानी)
झुंझुनूं	झाझड़–परसरामपुरा–धोलाखेड़ा (नवलगढ़)
	सुलताना–चनाना–बड़ाउ–कालोटा–बबाई (खेतड़ी)
	ढिगाल–मण्डावा (मण्डावा)
जोधपुर	लोहावट–देचू सड़क (लोहावट)
	जोधपुर–बालेसर–शेरगढ़ सड़क (शेरगढ़)
	गोकुल जी की प्याऊ से 8 मील मण्डोर तक तथा जोधपुर शहर की विभिन्न आंतरिक सड़कों पर स्टोन पेवमेंट (मण्डोर)
करौली	कुड़गांव से कैलादेवी (सपोटरा)
	फेली का पुरा से वाया कोटरी–खरैटा (हिण्डौन)
	केशपुरा बसेडी वाया सिरियापुरा (करौली)
कोटा	कैथून–राजपुरा–बालाजी की थाक–अडूसा–सांगोद पर उच्च स्तरीय पुल (सांगोद)
	इन्द्रगढ़–चम्बल ढीपरी–राजोपा–इटावा–पीपल्दा–शहनाबदा राज्य सीमा तक (इटावा, पीपल्दा)
	कोटा–सुल्तानपुर–खातौली–श्योपुर मार्ग पर सुल्तानपुर कस्बे में बाईपास (इटावा)
नागौर	डेगाना–हरसौर सड़क (डेगाना)
	जायल–मांगलोद–डेह सड़क (जायल)
	कुचामन–चितावा–घाटवा (कुचामन)
पाली	बिलाड़ा–सोजत–सिरियारी–देसूरी–सादड़ी–पिण्डवाड़ा (मारवाड़, देसूरी)
	जोधपुर–जोजावर सड़क स्टेट हाइवे–61 किमी. 227/0 से 250/0 वाया जैतपुरा–देवली–मुकनपुरा–जाणुन्दा–घनला–कोटड़ी (मारवाड़ जंक्शन)
	जैतारण से निम्बौल–सिनाल सड़क (जैतारण)
प्रतापगढ़	मंगलवाड़–बड़ी सादड़ी–छोटी सादड़ी–नीमच एवं नारायणी गांव बाईपास (छोटी सादड़ी)
	अरनोद–जाजली राज्य सीमा तक मय पुलिया (अरनोद)
	पुलिया निर्माण कार्य नकोर पीपलीखेड़ा रोड (गलिता नदी पर) (धमोतर)
राजसमंद	गुंजोल से सायों का खेड़ा (खमनोर)
	केलवाड़ा–ओलादर चौराहा से भादसोड़ा वाया सापोल–मुण्डोल–राजनगर–रेलमगरा–कपासन–भादसोड़ा चौराहा (राजसमंद)
	केलवाड़ा से सायरा सड़क (कुम्भलगढ़ सायरा)
सवाईमाधोपुर	सूरवाल खिलचीपुर गणेश धाम तक मय पुल (सवाई माधोपुर)
	सालोदा–पीलोदा–बगलाई शिवाला नादौती तक (गंगापुरसिटी)
	बहरावण्डा खण्डार बालेर सड़क से रामेश्वर घाट (खण्डार)
सीकर	खाटू–पलसाना–खण्डेला–चला (खंडेला)
	जाजोद से नरसास–डोआसरा–सोला–मंगलूणा सड़क (लक्ष्मणगढ़)
	कोटपूतली–लोसल वाया सीकर–धोद (धोद)
सिरोही	सिरोही–कालन्द्री–रामसीन (सिरोही)
	गिरवर चौराहे से (NH-27) मावल गांव तक सड़क मय पुल निर्माण (आबूरोड़)
	कोजरा–नादिया सड़क पर कोजरा नदी पर पुल निर्माण (पिण्डवाड़ा)
श्रीगंगानगर	गंगानगर बाईपास का उन्नयन (श्रीगंगानगर)
	सादुलशहर से पक्कासहारणा वाया प्रतापपुरा–मन्नीवाली–किल्लांवाली (सादुलशहर)
	पदमपुर से 32 एम.एल.सड़क (पदमपुर, रायसिंहनगर)
टोंक	नाथड़ी–पीपलू–रानोली–कठमाना (पीपलू)

ककोड़–नगर सड़क (उनियारा)
चतुर्भुजपुरा रोड से मुकुन्दपुरा वाया कीरों की ढाणी मय मासी नदी पर वेन्टेड काजवे (निवाई)

उदयपुर ऋषभदेव–बलुआ–सराड़ा–चावण्ड–जयसमंद–जगत झामेश्वर (ऋषभदेव, सलूंबर, सराड़ा)
दरोली–मंदेरिया–गुपड़ी–जसपुरा स्कूल होते हुए कुराबड़ सड़क तक (वल्लभनगर)
खैरवाड़ा–कल्याणपुर (सलूंबर)

- राज्य के कई नगरीय निकायों में समुचित वित्तीय संसाधन नहीं हैं। अत: एक विशेष फण्ड का गठन करते हुए, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 30 किलोमीटर, नगर परिषद की 20 किलोमीटर व नगर पालिका की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर लगभग 1 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–तृतीय के तहत आगामी दो वर्षों में शेष 2 हजार 841 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के कार्य किये जायेंगे। इस पर 1 हजार 425 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- प्रदेश के ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय, जो डामर सड़कों से वंचित है, को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा करता हूं।
- आगामी वर्ष में 3 हजार 880 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 590 किलोमीटर लम्बाई के 27 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	राज्य राजमार्ग	लागत
1.	ब्यावर–मसूदा–गोयला जिला अजमेर (SH-26A)	146 करोड़ 34 लाख रुपये
2.	अराई–सरवाड़ जिला अजमेर व टोंक (SH-7E)	111 करोड़ 24 लाख रुपये
3.	एन.एच.12–लक्ष्मीपुरा–डोरा–डाबी–राणाजी का गुढ़ा जिला बूंदी (SH-115)	103 करोड़ 25 लाख रुपये
4.	मांगलियावास–पादूकलां जिला अजमेर व नागौर (SH-102)	134 करोड़ 38 लाख रुपये
5.	ब्यावर–पीसांगन–टहला–कोट–अलनियावास जिला अजमेर व नागौर (SH-59&104)	132 करोड़ 77 लाख रुपये
6.	पदमपुर–रायसिंहनगर एवं सत्तासर–बीकानेर अनुभाग जिला श्रीगंगानगर व बीकानेर (SH-3)	206 करोड़ 35 लाख रुपये
7.	झुंझुनूं–राजगढ़ जिला झुंझुनूं व चूरू (SH-41)	151 करोड़ 47 लाख रुपये
8.	नीमकाथाना–खेतड़ी–सिंघाना जिला सीकर व झुंझुनूं (SH-13)	174 करोड़ 31 लाख रुपये
9.	किशनगढ़–अराई–मालपुरा जिला अजमेर व टोंक (SH-7E)	162 करोड़ 22 लाख रुपये
10.	रामसीन–भीनमाल रानीवाड़ा जिला जालौर (SH-31)	242 करोड़ 71 लाख रुपये
11.	दांतीवाड़ा–पीपाड़–मेड़ता सिटी खण्ड (SH-21)	240 करोड़ 85 लाख रुपये
12.	चूरू–तारानगर–नोहर खण्ड (SH-36)	258 करोड़ 74 लाख रुपये
13.	खेड़ली–नदबई–कुम्हेर खण्ड (SH-44)	118 करोड़ 12 लाख रुपये
14.	राजगढ़–भादरा खण्ड (SH-106)	126 करोड़ 72 लाख रुपये
15.	पालोदा–गढ़ी–आनन्दपुरी राज्य सीमा तक खण्ड (SH-10A)	107 करोड़ 71 लाख रुपये
16.	मथानिया–तिंवरी–देचू (SH-61B) और जोधपुर–तिंवरी (SH-95)	250 करोड़ रुपये
17.	धरियावाद–पारसोला–साबला (SH-91)	111 करोड़ 5 लाख रुपये
18.	गढ़ी–बागीदौरा–कुशलगढ़ (SH-54A)	179 करोड़ 14 लाख रुपये
19	नटनी का बाड़ा–मालाखेड़ा (अलवर)–मौजपुर (SH-44)	100 करोड़ 18 लाख रुपये
20.	बीकानेर–नापासर–जसरासर (SH-20B)	130 करोड़ रुपये
21.	सायला–बागौड़ा–गुढ़ामालानी (जालोर–बाड़मेर) (SH-16B)	172 करोड़ 50 लाख रुपये
22.	गोटन–साथिन (पीपाड़) (SH-86B)	61 करोड़ रुपये
23.	बूंदी–सिलोर–नमाना–गरदा–भोपतपुरारोड़ (SH-29B)	132 करोड़ रुपये
24.	गोल्याना–नवलगढ़ (MDR-25B)	54 करोड़ रुपये
25.	बम्बोरा (किशनगढ़ बास) (SH-25)–नौगांव (MDR-25 VR)	56 करोड़ 25 लाख रुपये
26.	माल बमोरी–मांगरोल–बारां खण्ड (SH-01)	125 करोड़ रुपये
27.	दूदू–सांभर–भाटीपुरा (SH-2)	90 करोड़ 90 लाख रुपये

- आगामी वर्ष में 403 करोड़ रुपये की लागत से हिण्डौन–करौली में तीन, बयाना–भरतपुर में दो, लाखेरी–बूंदी, भरतपुर शहर व गंगापुरसिटी–सवाई माधोपुर में एक–एक ROB का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक कुल रेल वाहन भार वाले 8 रेल फाटकों (आदर्श नगर–अजमेर में दो, दोराई–अजमेर, नोखा–बीकानेर, देपलसर–चूरू, रानीवाड़ा–जालोर, डेगाना–नागौर, पलसाना–सीकर में एक–एक) पर ROB के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करायी जायेगी।
- फतेहपुर–सीकर में सीकर–चूरू रेलवे खण्ड पर पूर्व समपार फाटक संख्या 32 पर 1 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से RUB का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।
- बूंदी जिले में कोटा–लाखेरी–सवाई माधोपुर–लालसोट–दौसा मेगा हाइवे पर पापड़ी गांव के पास मेज नदी पर 37 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से High Level Bridge का निर्माण कराया जायेगा।
- कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में इन्द्रगढ़–ढिबरी–राजोपा–इटावा–शहनावदा–ललितपुर सड़क (एसएच–120) पर स्थित गोठड़ा कलां पर चम्बल नदी पर High Level Bridge के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करवायी जायेगी।
- यातायात को सुगम बनाने के लिए खातोली–सवाई माधोपुर सड़क पर जरेल के पास चम्बल नदी पर 131 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया जायेगा। इसी के साथ, बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले को जोड़ने वाली नदी पर 132 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण किये जाने की मैं, घोषणा करता हूं।
- प्रदेश में स्थानीय आवश्यकतानुसार 50 एनिकटों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया जायेगा। साथ ही, सिलवट (राजाखेड़ा)–धौलपुर में पार्वती नदी पर 6 करोड़ रुपये की लागत से एनिकट बनाया जायेगा।
- जैसाकि विदित है, जयपुर की महत्त्वपूर्ण रिंग रोड योजना के पहले चरण में अजमेर रोड से आगरा रोड (दक्षिणी रिंग रोड) पर यातायात आरंभ हो गया है। अब द्वितीय चरण में आगरा रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाली 45 किलोमीटर लम्बी उत्तरी रिंग रोड की डीपीआर बनायी जायेगी।
- भरतपुर–आगरा वाया अछनेरा रोड की राजस्थान सीमा तक 15 किलोमीटर लम्बाई में सड़क को चौड़ा करने के लिए आगामी वर्ष में 16 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।
- आगामी वर्ष में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वाटिका, महला–जयपुर, निवाई–टोंक, नसीराबाद एवं किशनगढ़–अजमेर, आबूरोड–सिरोही, उदयपुर शहर, भींडर–उदयपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा में लगभग 3 हजार आवासों का निर्माण करवाया जायेगा।
- मेरे द्वारा माननीय सदस्यों के लिए विधानसभा के निकट आवास निर्मित करने की घोषणा की गयी थी। अब इसी परिसर में आवासों के साथ–साथ नई दिल्ली स्थित Constitution Club की तर्ज पर **Constitutional Club, Jaipur** बनाना प्रस्तावित करता हूं, जिससे पक्ष व विपक्ष के सभी साथियों में Legislative fraternity की भावना स्थायी रूप से बनी रहेगी।
- पाक विस्थापितों को सामाजिक एवं आर्थिक संबल देने की दिशा में 'विनोबा भावे नगर' के अंतर्गत 1700 विस्थापितों के लिए ग्राम चौखा–जोधपुर में 102 करोड़ रुपये की लागत से सस्ती दर पर आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- जयपुर शहर में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य करवाये जायेंगे। जिसमें जयपुर की पारम्परिक स्थापत्य कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। साथ ही, शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किया जायेगा।
- जयपुर में, आगरा रोड पर लगभग 113 हेक्टेयर भूमि पर

सिल्वन पार्क का विकास किया गया है। अगले चरण में, इसमें वॉकिंग–ट्रेक का निर्माण व अन्य विकास कार्य करवाकर सेन्ट्रल पार्क की तर्ज पर विकसित किया जायेगा।

- जोधपुर में जल भराव की समस्या दूर करने व ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए शोभावतों की ढ़ाणी से जोजरी नदी तक भैरव नाला का तथा सारण नगर से आरटीओ नाला का जोजरी नदी तक निर्माण कार्य करवाया जायेगा। इन पर 191 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। साथ ही, जोधपुर शहर में पुरानी सीवरेज लाइन की मरम्मत व नयी सीवरेज लाइन के कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 309 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- भरतपुर शहर के जल निकासी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जायेगा। इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- लक्ष्मणगढ़–सीकर में बरसात के दिनों में एकत्रित होने वाले पानी की निकासी के लिए पम्पिंग स्टेशन का निर्माण WWTP की स्थापना आदि कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
- धार्मिक नगरी पुष्कर–अजमेर के पवित्र सरोवर में बारिश के पानी के साथ गंदगी को जाने से रोकने संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु DPR बनायी जायेंगी।
- कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए महाराणा प्रताप चौराहा, कुन्हाड़ी का विकास कार्य एवं बोरखेड़ा ROB से पेट्रोलपम्प बारां रोड तक एलीवेटेड रोड़ का निर्माण किया जायेगा, जिस पर 140 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- जोधपुर शहर में बॉम्बे मोटर एवं 12वीं रोड से पावटा तक मुख्य सड़क के समानान्तर सड़कों का उपयोग करते हुए Looping Route विकसित करने के साथ–साथ हेरिटेज संरक्षण हेतु नई सड़क के बरामदों, रेलवे स्टेशन से राजरणछोड़ दास जी मंदिर होते हुए पूरी तिराहे तक के भवनों का जीर्णोद्धार तथा घण्टाघर से मेहरानगढ़ तक ब्ल्यू कॉरिडोर का कार्य कराया जायेगा। इन पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- पाली शहर की मुख्य सड़कों–सोजत रोड पर Government कॉलेज से लेकर हैफा हीरो सर्किल व जोधपुर रोड पर खेतेश्वर सर्किल तक निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये लागत के कार्य करवाये जायेंगे।
- बीकानेर शहर में गोगा गेट सर्किल से भीनासर ट्रैफिक चौकी तक एवं म्यूजियम सर्किल से हल्दीराम प्याऊ तक की सड़क को 4 लेन से 6 लेन व पुगल फांटे से ROB तक सड़क विस्तारीकरण का कार्य करवाया जायेगा। साथ ही, वर्षा जल निकासी हेतु नालों का निर्माण किया जायेगा। इन कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- उदयपुर शहर में यातायात सुगमता एवं आधारभूत संरचना विकास की दृष्टि से भुवाना चौराहे से प्रतापनगर तक 4 लेन की 5.5 किलोमीटर इनर रिंग रोड का निर्माण, प्रतापनगर–भुवाना 200 फीट सड़क पर अण्डरपास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण व साउथ विस्तार योजना में सड़क निर्माण आदि कार्य कराये जायेंगे। साथ ही, वाडा–ढिकली क्षेत्र में जल भराव समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण, पहाड़ी–वाटरबॉडीज सरंक्षण एवं पेयजल सुविधा हेतु कार्य प्रारंभ कराये जायेंगे। इन कार्यों पर 150 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।
- अलवर शहर की शालीमार योजना में सीवरलाइन एवं STP निर्माण कार्य, वैशालीनगर से MIA तक 4 लेन सड़क एवं नाला निर्माण हीराबास काली मोरी से 200 फीट बाईपास तक एवं रूपवास ROB से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण कार्य किये जायेंगे। इन कार्यों पर अनुमानित 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- सवाई माधोपुर शहर में भैंरू दरवाजे के पास से राजबाग तक की सड़क के विकास व सौन्दर्यीकरण हेतु DPR बनायी जायेगी।
- जोधपुर शहर में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 500 की बैठक क्षमता के **आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर** का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, दौसा, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवं बूंदी में टाउनहॉल बनाये जायेंगे।
- हमने वर्ष 2012–13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं, नये वाहनों के साथ **ग्रामीण बस सेवा** पुन: प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़ा जायेगा। साथ ही, करौली व लाडनूं, मकराना–नागौर में आधुनिक रोडवेज बस स्टैण्ड व बानसूर–अलवर में नवीन बस डिपो बनाये जायेंगे।

- सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं मानवीय हस्तक्षेप को नगण्य करने हेतु 5 जिलों–प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, बूंदी एवं बारां में ऑटोमैटेड फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पर 10 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

पेयजल-जल संसाधन

- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 4 हजार 700 करोड़ रुपये की 12 नवीन वृहद् पेयजल परियोजनाओं का काम प्रारंभ किये जाने की घोषणा करता हूं। इससे 1 हजार 428 गांव एवं 1 हजार 891 ढाणियां लाभान्वित होंगी। ये परियोजनायें हैं–
  - बाड़मेर लिफ्ट परियोजना भाग 'अ' (बाड़मेर–बायतु–बालोतरा) जिला बाड़मेर व बाड़मेर लिफ्ट परियोजना भाग 'द' (भणियाना, सांकड़ा, सम, फतेहगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर) जिला जैसलमेर।
  - कानसिंह की सिड–मंडोर परियोजना (बाप), फलौदी जिला जोधपुर व राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से पीलवा–सादड़ी जंबेश्वर नगर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना (लोहावट एवं देचूं) जिला जोधपुर एवं माणकलाव–दाईजर–बनाड़ (मण्डोर–कैरू–ओसियां) जिला जोधपुर।
  - आपणी योजना–द्वितीय चरण (रतनगढ़–सुजानगढ़ सेक्शन) जिला चूरू
  - फतेहपुर–लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना जिला सीकर।

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1.	भेर–हरलाया भाग प्रथम वृहद् पेयजल परियोजना (ओसिया) जिला जोधपुर	136 करोड़ 36 लाख रुपये
2.	भेर–हरलाया भाग द्वितीय वृहद् पेयजल परियोजना (आऊ–लोहावट एवं बापिणी) जिला जोधपुर	463 करोड़ 10 लाख रुपये
3.	बत्तीसा नाला वृहद् पेयजल परियोजना (सिरोही–पिण्डवाड़ा–आबू रोड) जिला सिरोही	408 करोड़ 24लाख रुपये
4.	शिवगंज वृहद पेयजल परियोजना जिला सिरोही	294 करोड़ 9 लाख रुपये
5.	नर्मदा केनाल (ईआर) आधारित क्लस्टर जल प्रदाय परियोजना (जसवंतपुरा–रानीवाड़ा–सांचोर–सरनाऊ–चितलवाना–बागौड़ा–भीनमाल–जालोर–सांयला) जिला जालोर	1 हजार 94 करोड़ रुपये
6.	माही बांध से पंचायत समिति घाटोल एवं बांसवाड़ा के कुल 249 गांवों हेतु पेयजल परियोजना जिला बांसवाड़ा	500 करोड़ रुपये
7.	श्री डूंगरगढ़ लूणकरणसर जल प्रदाय परियोजना जिला बीकानेर	708 करोड़ 93 लाख रुपये
8.	खाजूवाला जल प्रदाय परियोजना जिला बीकानेर	488 करोड़ 89 लाख रुपये
9.	राजगढ़–झालरापाटन जल प्रदाय परियोजना जिला झालावाड़	274 करोड़ 78 लाख रुपये
10.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाघेरी का नाका जिला राजसमन्द	133 करोड़ 48 लाख रुपये
11.	तहसील बेगूं के 62 गांवों एवं 36 ढाणियों को सतही पेयजल स्रोत ओराई बांध आधारित परियोजना जिला चित्तौड़गढ़	44 करोड़ 49 लाख रुपये
12.	जायल मातासुख पेयजल परियोजना जिला नागौर	159 करोड़ 30 लाख रुपये

- जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 13 परियोजनाओं की DPR बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से आगामी वर्ष में, प्रथम चरण में 2 हजार 285 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिससे प्रदेश के 2 हजार 686 गांव एवं 2 हजार 453 ढाणियां लाभान्वित होंगे। ये परियोजनायें हैं–
  - क्लस्टर परियोजना आसींद–बदनोर, बनेड़ा–हुरड़ा, रायपुर–सहाड़ा–सुवाणा, जहाजपुर–कोटड़ी, मांडलगढ़–बिजोलिया–जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
  - इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एकीकृत तारानगर–झुंझुनूं, सीकर खेतड़ी, वृहद् पेयजल परियोजना जिला झुंझुनूं।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जायेगा।
- वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन के कार्य हेतु 3 हजार 233 गांवों व 2 हजार 606

ढाणियों के लिए 22 परियोजनाओं की DPR तैयार की जायेंगी, जो इस प्रकार हैं–

- बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण–क्लस्टर पार्ट – 'ब' (बाड़मेर–बायतु–सिणधरी) जिला बाड़मेर।
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलौदी हैडवर्क्स–बावड़ीकला–खारा–जालौड़ा एवं राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल RD-42 घाटौर–कानासर–बाप (बाप, फलौदी, लोहावट) जिला जोधपुर।
- मलार–जोड़–हिंडाल गोल (बाप, फलौदी) जिला जोधपुर।
- जवाई प्रोजेक्ट क्लस्टर प्रथम (बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, सुमेरपुर), द्वितीय (पाली मारवाड़ जंक्शन व रानी) व तृतीय (जैतारण, रायपुर व सोजत) जिला पाली।
- क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मंडली, जैतपुर, पुख्तारी (रोहट) जिला पाली।
- नर्मदा एफआर (जालौर, सांचौर, चितलवाना, बागौड़ा, आहोर, सायला) एवं डीआर क्लस्टर (जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर, सरनऊ) जिला जालौर।
- कोलायत जल प्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट एवं कोलायत लिफ्ट) जिला बीकानेर
- बूंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला चूरू।
- आपणी योजना एवं सरदार शहर के 60 गांवों के संवर्धन पेयजल परियोजना जिला चूरू एवं हनुमानगढ़।
- गुलण्डी एवं कालीखाड जल प्रदाय योजना जिला झालावाड़।
- पीपलाद पेयजल परियोजना जिला झालावाड़।
- चंबल बूंदी क्लस्टर पेयजल परियोजना जिला बूंदी।
- सिंगोला पेयजल परियोजना जिला बारां।
- चंबल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं के 433 गांवों की पेयजल परियोजना।
- बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना जिला कोटा।
- छापी झालावाड़ झालरापाटन पेयजल परियोजना जिला झालावाड़।

- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 476 करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1.	बाड़ी–धौलपुर में उच्च जलाशयों की क्षमता बढ़ाने स्रोतों का निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के पुनर्गठन कार्य	38 करोड़ रुपये
2.	बाड़मेर शहर में उच्च जलाशयों के निर्माण व नयी पाइप लाइन बिछाने संबंधी कार्य	10 करोड़ रुपये
3.	उदयपुर जिले के कानोड़, फतहनगर–सनवाड़ एवं उदयपुर शहर में उच्च जलाशयों का निर्माण, पाइप लाइन बिछाने इत्यादि कार्य	35 करोड़ रुपये
4.	जयपुर शहर के डिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड के बीच के क्षेत्र एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में बीसलपुर योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु	115 करोड़ रुपये
5.	जयपुर शहर के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा एवं बढ़ारना क्षेत्र की पेयजल की स्थायी आधारभूत व्यवस्था हेतु पृथ्वीराज नगर के ट्रांसमिशन सिस्टम से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु	41 करोड़ रुपये
6.	शाहपुरा एवं विराटनगर, जिला–जयपुर में उच्च जलाशय एवं पाइप लाइन इत्यादि के कार्य	38 करोड़ रुपये
7.	सीकर, लोसल एवं नीमकाथाना क्षेत्र में पेयजल योजना के संवर्द्धन संबंधी कार्य	17 करोड़ रुपये
8.	जिला डूंगरपुर के गलियाकोट एवं चित्तरी–बड़गी जल योजना के पुनर्गठन संबंधी कार्य	33 करोड़ रुपये
9.	भीनमाल जिला जालौर में पेयजल समस्या निराकरण के कार्य	50 करोड़ रुपये
10.	उदयपुर जिले के वल्लभनगर, भीण्डर, कुराबड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी कार्य	65 करोड़ रुपये
11.	राजसमंद की पंचायत समिति राजसमंद एवं रेलमगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी कार्य	30 करोड़ रुपये
12.	सहाड़ा–भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र–सहाड़ा, कोशीथल एवं पोटला में जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं सुधार कार्य	4 करोड़ रुपये

- **चम्बल–भीलवाड़ा पेयजल परियोजना** के अंतर्गत राजसमन्द की भीम व देवगढ़ तहसीलों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु DPR बनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021–22 में 1 हजार 32 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कर आगामी तीन वर्षों में पूर्ण किया जायेगा। इससे भीम पंचायत समिति के 141 गांव व 633 ढाणियां एवं देवगढ़ पंचायत समिति के 134 गांव व 194 ढाणियां तथा देवगढ़ कस्बे की जनता पेयजल सुविधा से लाभान्वित होंगी।
- भीलवाड़ा जिले में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमारे पिछले कार्यकाल में **चम्बल–भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, द्वितीय–चरण** स्वीकृत की गई थी। गत सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह परियोजना पूरी नहीं हो पयी। अब, इसको पूरा किये जाने के लिए अतिरिक्त 948 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
- वर्ष 2020–21 में मैंने, बीसलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत पंचायत समिति केकड़ी सरवाड़ एवं सावर के 192 गांव एवं 99 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु DPR बनाने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में, 725 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
- **पोकरण–फलसूण्ड–बालोतरा–सिवाणा वृहद पेयजल परियोजना** में वर्ष 2038 की पेयजल मांग के अनुरूप पोकरण लिफ्ट के स्थान पर इंदिरा गांधी मुख्य नहर से पानी लिया जाना है। परियोजना में अतिरिक्त 580 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इससे बालोतरा, सिवाणा कस्बे एवं बाड़मेर के 386 गांव लाभांवित होंगे।
- **नोखा–बीकानेर पेयजल परियोजना** हेतु वर्ष 2020–21 में DPR बनाने की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष में, 750 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इससे नोखा एवं बीकानेर पंचायत समिति के 137 गांव एवं कोलायत क्षेत्र के 9 गांवों की जनता लाभान्वित होगी।
- ईसरदा बांध परियोजना दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु महत्त्वपूर्ण है। इस परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1 हजार 394 गांव व अलवर जिले की उमरेण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के 4 कस्बों एवं 1 हजार 61 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 12 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनायी जायेगी।
- कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोद, सीकर, खंडेला, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर व नीमकाथाना के शेष रहे 864 गांवों एवं 13 कस्बों तथा झुंझुनूं जिले की तहसील चिड़ावा, नवलगढ़ के 269 गांवों एवं 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की इस योजना की लागत 7 हजार 700 करोड़ रुपये होगी। आगामी वर्ष में इसके कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।
- राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज–तृतीय आधारित 1 हजार 458 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना की वर्ष 2020–21 में घोषणा की गयी थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु जायका (JICA) से वित्त पोषण की व्यवस्था की गयी है। इसके कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ किये जायेंगे।
- झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ कस्बे तथा 921 गांवों व 573 ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आगामी वर्ष में जायका द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।
- माननीय सदस्यों के माध्यम से पेयजल समस्या संबंधी प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवेल तक लगवाये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, डीडवाना–नागौर, नारायणपुर–अलवर, कामां–भरतपुर, फागलिया–बाड़मेर में AEn Office व कुचामनसिटी–नागौर में Ex En Office खोला जायेगा।
- जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं–राजीव गांधी नगर, रामराज नगर, ढेगड़ी–चौखा, आरके पुरम–चौखा, सुन्दर सिंह भण्डारी नगर, मण्डलनाथ आवास, लौहड़ी, पंडितजी, विजयराजे सिंधिया नगर, मोगड़ा, कर्मचारी कॉलोनी, मोगड़ा ट्रांसपोर्ट योजना में पेयजल की सुचारू व्यवस्था हेतु लगभग 76 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी 37 हजार करोड़ रुपये लागत की **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)** को धरातल पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक

जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु **ERCP** परियोजना बनायी गयी, जो कि बाड़मेर रिफाइनरी के पश्चात् प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है।

- मैं हमारे विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 7 जुलाई, 2018 एवं 6 अक्टूबर, 2018 को जयपुर व अजमेर की सभाओं में किये वादे के अनुसार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। 20 फरवरी, 2021 को नीति आयोग की बैठक के दौरान भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा पुन: याद दिलाते हुए आग्रह किया कि उनका वादा उन्हें ही पूरा करना है। साथ ही बताया कि, इस प्रकार की 16 अन्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया हुआ है। ये परियोजनायें–असम, आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में स्थित हैं। अत: राजस्थान की ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना, समझ से परे है तथा प्रदेश के साथ भेदभाव की श्रेणी में आता है।
- हालांकि केन्द्र ने हमारे निरंतर आग्रह के पश्चात् भी इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराये हैं। परन्तु, हम अपने संसाधनों से इसका कार्य जारी रखेंगे। परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर प्रगतिरत नवनेरा बैराज के निर्माण पर 167 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं तथा द्वितीय चरण में नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक का कार्य आरंभ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, धौलपुर में 60 करोड़ रुपये की लागत से कालीतीर लिफ्ट परियोजना कार्य भी शुरू किया जायेगा। इनके लिए मैं, कुल 320 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं।
- बारां–झालावाड़–कोटा जिलों की महत्त्वाकांक्षी **परवन वृहद् सिंचाई परियोजना** को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाये जाने हेतु हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में, ERCP के साथ ही इस परियोजना के लिए भी मंत्रिमण्डल प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को आग्रह किया जा चुका है। परियोजना के बांध व टनल निर्माण कार्यों के साथ–साथ, लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में प्रेशराइज्ड पाइप तकनीक से कमाण्ड क्षेत्र विकसित करने के कार्य प्रगति पर हैं। योजना पर अब तक लगभग 3 हजार 300 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मैं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 885 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं।
- राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project-RWSLIP) के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। आगामी वर्ष में, इस परियोजना पर 465 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, जिससे 21 जिलों के 2 लाख 62 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लगभग 5 लाख काश्तकार लाभांवित होंगे।
- रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area-RWSRPD) में लगभग 378 करोड़ रुपये की लागत से 49 किलोमीटर लंबाई में इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर तथा वितरिकाओं एवं माईनरों के जीर्णोद्धार कार्य करवाये जायेंगे।
- राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर की रिलाइनिंग के कार्यों पर आगामी वर्ष में 250 करोड़ रुपये व्यय किय जायेंगे।
- आगामी वर्ष में **रिपेयर–रिनोवेशन–रेस्टोरेशन** (RRR) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 14 जिलों–जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, टोंक, भरतपुर, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां एवं बूंदी के विभिन्न जलाशयों में 124 करोड़ 71 लाख रुपये के 37 कार्य किये जायेंगे। इससे 7 हजार 380 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाकर लगभग 2 लाख किसानों को लाभांवित किया जायेगा।
- हमारी सरकार बांधों के समग्र जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2020–21 के बजट में मैंने, **बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP)** के अंतर्गत 18 बांधों के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में, 70 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से 18 और बांधों–जग्गर (हिण्डौन)–करौली, बरेठा–बयाना–भरतपुर, मोरा सागर (बामनवास)–सवाई माधोपुर, सिलीबैरी (उमरेण)–अलवर, सैथल सागर–दौसा, नन्दसमंद (नाथद्वारा)–राजसमंद, वागन (डूंगल), बड़ी मानसरोवर (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़, भवंरसैमला (पीपलखूंट)–प्रतापगढ़, सुरवानिया– बांसवाड़ा, गोवटा (मांडलगढ़) एवं मेजा (मांडल)–भीलवाड़ा, चिनार (आबू रोड), कादम्बरी एवं कैर (पिण्डवाड़ा)–सिरोही बांकली (आहोर)–जालौर, सादड़ी (देसूरी)–पाली एवं भीमलत (हिण्डौली)–बूंदी के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।

- **इंदिरा गांधी नहर परियोजना–द्वितीय चरण** की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 1 हजार 658 करोड़ 81 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी थी, परंतु केन्द्र सरकार द्वारा अपनी पूर्ण हिस्सा राशि नहीं दी गई तथा बाद में इस योजना को बंद कर दिया। अब चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर व जोधपुर जिलों के कृषकों को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए, 3 लिफ्ट योजनाओं–चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट एवं करणी सिंह लिफ्ट के कार्यों हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेंगे।
- आमजन की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में धूलेट खानपुर मार्ग में कालीसिंध नदी पर बनी पुलिया को एनिकट में बदला जायेगा। इससे 180 लाख क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल संग्रहीत किया जा सकेगा।
- खाजूवाला–बीकानेर की धौधा, भुट्टोवाली वितरिका एवं बिरसलपुर शाखा का 135 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जायेगा।

ऊर्जा

- माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से **ऊर्जा नीति : 2021–2050** जारी की जायेगी।
- हमारी सरकार ने गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011 में सौर ऊर्जा नीति एवं वर्ष 2012 में पवन ऊर्जा नीति जारी की थी। इसके फलस्वरूप, आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता 5002 मेगावाट हो गयी है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। साथ ही, राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता भी 4337 मेगावाट हो चुकी है।
- सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का **ग्रीन कॉरिडोर** विकसित करना प्रस्तावित है, जिससे राज्य के पोकरण, रामगढ़–जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तथा जोधपुर जिले में अक्षय ऊर्जा की नयी परियोजनायें शुरु की जा सकेंगी।

- गत दो वर्षों के दौरान छबड़ा में 660 मेगावाट एवं सूरतगढ़ में 660 मेगावाट की तापीय परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सूरतगढ़ क्रिटिकल तापीय परियोजना की एक और इकाई (इकाई–8) से 660 मेगावाट का वाणिज्यिक उत्पादन जून माह तक प्रारम्भ हो जायेगा।
- राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए–
  - बागावास अहिरान (विराटनगर)–जयपुर तथा बेगूं गंगरार– चित्तौड़गढ़ में 33 केवी के जीएसएस बनाये जायेंगे। साथ ही, माणकासर डूंगरगढ़ (खाजूवाला)–बीकानेर में 33 केवी जीएसएस का विस्तार किया जायेगा।
  - नारायणपुर–अलवर, मण्डरायल–करौली, फागलिया (चौहटन)
  - बाड़मेर, मलारना डूंगर–सवाई माधोपुर तथा सीकरी–भरतपुर में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय खोले जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण

- जनजाति क्षेत्रों में **सामुदायिक वन अधिकार** पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर, 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए Commissioner TAD की अध्यक्षता में Task Force का गठन किया जायेगा।

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर विश्व में पक्षियों की शरणस्थली के रूप में विख्यात है। यह यूनेस्को हेरिटेज एवं रामसर Recognised साइट है। इसके महत्त्व को देखते हुए इसे Wetland Birds Habitat Conservation Centre के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही, जैव विविधता के संरक्षण एवं पक्षियों हेतु जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए चम्बल नदी से जल लाने के लिए लगभग 570 करोड़ रुपये की योजना की DPR तैयार की जायेगी।
- तालछापर अभयारण्य, चूरू में **वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र** स्थापित किया जायेगा।
- चम्बल घड़ियाल अभयारण्य के खण्डार–सवाई माधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करवाये जायेंगे।
- जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर के कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपये की लागत से वॉकिंग ट्रेक, योगापार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधायुक्त **'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन'** स्थापित करने की घोषणा करता हूं।
- राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए **'घर–घर औषधि योजना'** शुरु की जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।
- राज्य के ऐसे शहरों में जहां सीवरेज सुविधा नहीं हैं वहां पर दो वर्षों में Faecal (फिकल) Sludge Treatiment Plants (FSTP) स्थापित किये जायेंगे। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष में, 24 जिलों के 50 शहरों में FSTP लगाये जायेंगे, जिस पर 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये शहर हैं–

जिला	शहर
अजमेर	केकड़ी, बिजयनगर
अलवर	बहरोड़, खैरथल, थानागाजी
बारां	छबड़ा, अंता
बीकानेर	डूंगरगढ़
भरतपुर	बयाना, रूपबास
भीलवाड़ा	गुलाबपुरा, मांडलगढ़, आसींद
बूंदी	लाखेरी
चित्तौड़गढ़	रावतभाटा
चूरू	राजगढ़, राजलदेसर, तारानगर, बीदासर
धौलपुर	राजाखेड़ा
डूंगरपुर	सांगवाड़ा
हनुमानगढ़	नोहर, संगरिया, रावतसर
श्रीगंगानगर	अनूपगढ़, केसरीसिंहपुरा
जयपुर	कोटपूतली, किशनगढ़–रेनवाल, चाकसू
जालोर	भीनमाल, सांचोर
जोधपुर	पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा
झुंझुनूं	उदयपुरवाटी, पिलानी, बगड़, विद्या विहार (पिलानी)
कोटा	रामगंज मंडी
नागौर	डेगाना, मेड़तासिटी, परबतसर
पाली	सोजत, सादड़ी, रानी
सिरोही	शिवगंज
सीकर	लोसल, श्रीमाधोपुर
टोंक	टोंक, निवाई
उदयपुर	सलूंबर

- हमारे द्वारा पृथ्वीराज नगर–जयपुर के निवासियों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम की डीपीआर का कार्य पूरा कर लगभग 200 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।
- अस्पतालों के Liquid एवं Solid Waste का निस्तारण पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में प्रदेश के बड़े अस्पतालों RUHS, SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय–जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल–जोधपुर, पीबीएम अस्पताल–बीकानेर तथा मेडिकल कॉलेज–कोटा से संबद्ध अस्पतालों में 25 करोड़ रुपये की लागत से Sewerage Treatrnent Plants स्थापित किये जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु पिछले वर्ष मैंने **पर्यटन विकास कोष**

के गठन की घोषणा की थी। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए अब मैं, आगामी वर्ष में पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करता हूं। इसमें 200 करोड़ रुपये प्रदेश की Tourist Destination के रूप में Branding करने तथा 300 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना व निवेश आदि के लिए खर्च किये जायेंगे।

- **शेखावाटी पर्यटन सर्किट** विकसित किया जायेगा, जिसमें लोहार्गल, शाकम्भरी माता मंदिर, हर्षनाथ पहाड़ी, जीणमाता मंदिर, नवलगढ़, डूंडलोद, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ शेखावाटी, महनसर, अलसीसर, मलसीसर एवं खेतड़ी सम्मिलित किये जायेंगे। साथ ही, पर्यटक सूचना केन्द्र, सीकर को पर्यटक स्वागत केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।
- पाली के रणकपुर क्षेत्र, सोनाणा खेतलियाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र व बाली दुर्ग, जालौर के सुंधा माता व जालौर दुर्ग बाड़मेर के आसोतरा, सिरोही के अर्बुदा धाम, अधर देवी, अचलगढ़, मारकुण्डेश्वर धाम, अम्बेश्वर जी व भेरूतारक धाम आदि स्थलों को **गोडवाड़ पर्यटन सर्किट** के रूप में विकसित किया जायेगा।
- RTDC द्वारा संचालित Midway यात्रियों में काफी लोकप्रिय रहे हैं। इनमें से 7 महत्त्वपूर्ण Midway इकाइयों बर–पाली, बहरोड़–अलवर, रतनगढ़–चूरू, पोकरण–जैसलमेर, फलौदी–जोधपुर, देवगढ़–राजसमंद एवं शाहपुरा–जयपुर का 10 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कर सुचारु संचालन किया जायेगा।
- राज्य में **सर्वधर्म समभाव** को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख **हिन्दू तीर्थस्थलों** जैसे चारभुजा, नाथद्वारा–राजसमंद, गौतम ऋषि मंदिर–सिरोही, पुष्कर–अजमेर, कोलायात–बीकानेर, खाटूश्यामजी–सीकर, मेहंदीपुर बालाजी–दौसा, डिग्गी कल्याणजी–टोंक, प्रमुख **जैन तीर्थस्थलों** यथा तिजारा–अलवर, श्रीमहावीरजी–करौली, चमत्कारजी–सवाई माधोपुर, बाड़ापदमपुरा, सांगानेर–जयपुर, देलवाड़ा, अचलगढ़, माउंट आबू–सिरोही, रणकपुर–पाली व चांदखेड़ी–खानपुर–झालावाड़, प्रमुख **सिख तीर्थस्थलों** यथा बुड्डा जोहढ़–श्रीगंगानगर, नरायना, खालसा हैरिटेज

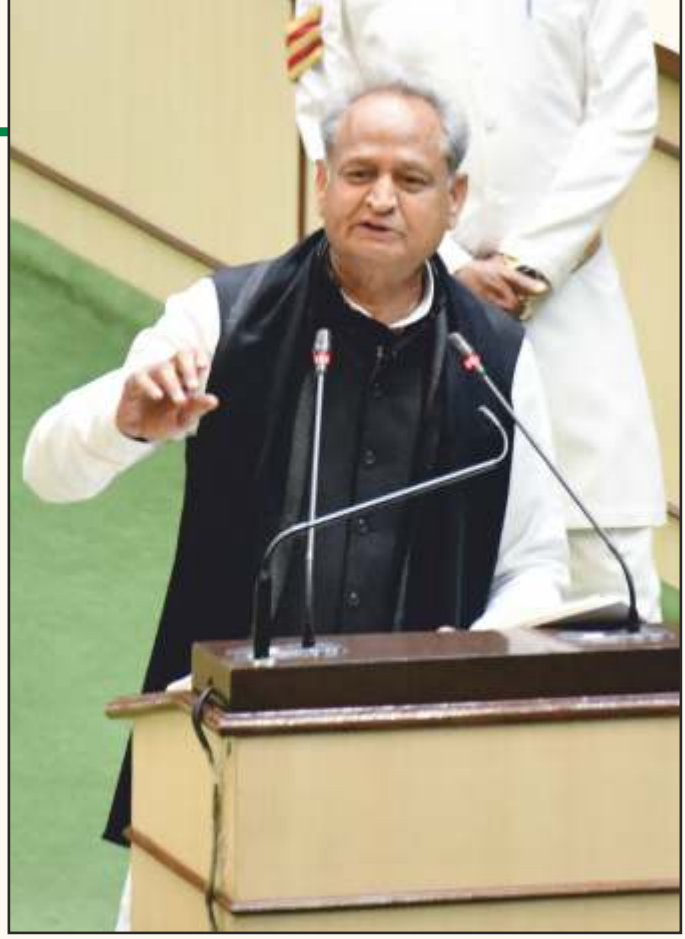

कॉम्पलेक्स–जयपुर, पुष्कर–अजमेर, गुरु द्वारा श्री कलगीधर–बागौर साहिब व माण्डल–भीलवाड़ा तथा प्रमुख **मुस्लिम तीर्थस्थलों** यथा सरवाड़ दरगाह–अजमेर, दरगाह तन्हा पीर मण्डोर–जोधपुर, दरगाह कपासन–चित्तौड़गढ़, हमीदुद्दीन दरगाह–नागौर, मिठ्ठेशाह दरगाह–झालावाड़, नरहड़ की दरगाह–झुंझुनूं, हकीम साहब की दरगाह–सीकर, दरगाह मीर कुर्बान अली, दरगाह चारदरवाजा व दरगाह सांभर–जयपुर के **धार्मिक पर्यटन सर्किट** बनाये जायेंगे। इस पर 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

- उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा एवं आकर्षण हेतु फतेहसागर में स्थित नेहरू पार्क, रानी–रोड़ तथा मायरा की गुफा (महाराणा प्रताप शस्त्रागार), गोगुन्दा के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यों पर 19 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
- जोधपुर में मेहरानगढ़ किले में जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बालसमंद घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले तक सड़क मार्ग के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, माचिया किले के संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास के कार्य 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
- पर्यटकों के आकर्षण एवं मनोरंजन हेतु पुष्कर–अजमेर स्थित होकरा में 90 हैक्टेयर में तथा सूरजकुण्ड में 150 हैक्टेयर में Tourist Complex हेतु बहुउद्देशीय योजना बनाई जायेगी।

- देशी–विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह जैसलमेर में Tourism को बढ़ावा देने के लिए **ढोला मारू Tourist Complex** बनाने की घोषणा करता हूं। यह Complex मूलसागर एवं अमर सागर सम रोड़ पर लगभग 3500 बीघा भूमि पर बनाया जायेगा। इसमें पर्यटकों के आकर्षण व मनोरंजन हेतु रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउस आदि स्थापित किये जायेंगे। इसकी DPR के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसी कॉम्पलेक्स में **Rajasthan Folk Art Training Institute** की स्थापना भी की जायेगी।
- लक्ष्मणगढ़–सीकर के धार्मिक पर्यटक स्थल–श्री सांगलपति आश्रम, कुमास जागीर, गुलाबजति आश्रम–गाड़ोदा, श्री गोसांई मंदिर–कटेवा, गोविन्दर नाथ जी आश्रम–डूडवा एवं भक्त शिरोमणि कर्माबाई मंदिर–घस्सू का बास में विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे।
- पांचोताकुण्ड (नावां)–नागौर, ऐतिहासिक पुरास्थल घाट की गुणी–जयपुर, सर्वेश्वर मंदिर स्थल–बांसवाड़ा, राजा मोरध्वज नगरी गढ़मौर (टोड़ाभीम)–करौली, जोगणिया माता (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, बिजवामाता मंदिर मोदपुर–(आसपुर)–डूंगरपुर व बलेश्वर (नीमकाथाना)–सीकर आदि पर्यटक केन्द्रों के विकास कार्य करवाये जायेंगे।
- राज्य में Day Tourism, Rural Tourism Tribal Tourism व Adventure Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Viability Gap Funding योजना लायी जायेगी। इसके अंतर्गत छोटे पर्यटक स्थलों यथा खींचन, खेजड़ली, ओसियां–जोधपुर, भानगढ़–अलवर, सांभर, सामोद–जयपुर व अन्य स्थलों को विकसित करने तथा मुख्य पर्यटक स्थलों से जोड़ने के लिए Luxurey Tourist वाहनों का संचालन किया जायेगा।
- प्रदेश के जरूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध कराने, राजकीय संरक्षण प्रदान करने, उनके कल्याण एवं संबल के लिए **कलाकार कल्याण कोष** में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
  - राजस्थान को Film Destination के रूप में Promote करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति** लागू की जायेगी। इससे राजस्थानी भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत–
  - राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपये तक का Incentive Support दिया जायेगा।
  - राजस्थानी फिल्मों हेतु SGST में शत प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
  - राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण हेतु Viability Gap Funding दी जायेगी।
  - समस्त स्वीकृतियों के लिए Single Window Clearance System अपनाया जायेगा।
- प्रदेशभर के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए सभी जिलों में 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर **'राजस्थान उत्सव'** का आयोजन किया जायेगा।
- राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10 हजार प्रतिभाशाली युवाओं, कलाकारों एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए Nehru Youth Cultural Exposure Programme चलाया जायेगा।

कानून व्यवस्था

- माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि आजादी के कई वर्षों बाद भी थानों में FIR दर्ज करवाना कितना कठिन काम था। पहले लोग मारे–मारे फिरते थे, फिर भी FIR दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2019 में थानों में FIR निर्बाध रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित किया। पहले आम धारणा थी कि ज्यादा FIR होने का मतलब है कि ज्यादा अपराध होना परन्तु FIR अनिवार्य करने से संख्या बढ़ सकती है, किन्तु पीड़ितों को न्याय मिलता है और यही बात **नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो** की वार्षिक रिपोर्ट में देखने को मिलती है।

माननीय सदस्यों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आंकड़ों के मायाजाल व अनावश्यक आलोचना से बचकर हमारे इस कदम को Appreciate करें।

हमने महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित जांच के लिए हर पुलिस जिले में **Special Investigation Unit for Crime Against Women** का गठन कर वहां महिला अधिकारी तैनात किये। इसके अलावा, जघन्य अपराधों के पर्यवेक्षण एवं

अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर **Heinous Crime Monitoring Unit** स्थापित की है। थानों में आने वाले पीड़ित नागरिकों को सकारात्मक माहौल मिले इस हेतु अब तक राज्य के 341 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बना दिये हैं और बाकी पुलिस थानों में भी यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

ये सभी कदम हमारी सरकार की संवेदनशीलता के परिचायक हैं। राज्य में त्वरित न्याय की सुविधा उपलब्ध कराने, अपराधों की रोकथाम करने व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ–साथ पुलिस को आधुनिक एवं सशक्त बनाये जाने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं–

- लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों (Medical Colleges) की DNA Finger Printing सुविधाओं एवं विशेषज्ञों की सेवायें लेते हुए, जांच सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।
- प्रदेश में जघन्य अपराधों की रोकथाम, आदतन अपराधियों की पहचान एवं आपराधिक रिकॉर्ड रखे जाने हेतु Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।
- आगामी वर्ष में, कुचामन–नागौर, बामनवास–सवाई माधोपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बानसूर–अलवर, तारानगर–चूरू, लोहावट–जोधपुर, नदबई–भरतपुर व आसपुर–डूंगरपुर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा बगरू–जयपुर में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय खोले जायेंगे।
- प्रदेश के मौजमाबाद (दूदू), रेनवाल मांझी–जयपुर, नोहर–हनुमानगढ़, चौरासी, ओबरी–डूंगरपुर, कल्याणपुर (खैरवाड़ा)–उदयपुर तथा रिफाइनरी पचपदरा–बाड़मेर में नये पुलिस थाने खोले जायेंगे। साथ ही, बार (भीम–देवगढ़)–राजसमंद, भाब्रू (विराटनगर)–जयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा तथा मालाखेड़ा–अलवर ग्रामीण, साड़ास (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, गांधीनगर (किशनगढ़)–अजमेर थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 25 नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जायेंगी।
- राज्य में नकली नोट, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंककारी गतिविधियों, गैरकानूनी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी एवं कार्यवाही हेतु राजगढ़–चूरू में एसओजी तथा बीकानेर व भरतपुर में एटीएस की चौकियां बनायी जायेंगी। साथ ही, जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा, SMS Hospital Jaipur तथा जयपुर–अजमेर Highway पर अपराधों के नियंत्रण हेतु जयपुर आयुक्तालय में तीन नवीन थाने बनाये जायेंगे।
- जयपुर एवं जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की वर्तमान संचार प्रणाली को बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से APCO Phase II Digital Radio Trunking System स्थापित किया जायेगा।
- Rajasthan Police Housing Construction Corporation को और व्यापक बनाते हुए Rajasthan Police Infrastructure Development Corporation के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा।
- प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधायें बेहतर करने के क्रम में कैदियों के रहने की बैरक, भोजनशाला एवं शौचालयों इत्यादि की मरम्मत–सुदृढ़ीकरण, 40 खुले बंदी शिविरों में 240 आवासों का निर्माण, 26 जिला कारागृहों में एम्बुलेंस एवं सुरक्षा उपकरण जैसे Non Linear Junction Detector (NLJD) इत्यादि उपलब्ध कराने तथा उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन पर लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी।
- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के क्रम में संदिग्ध टेलीफोन कॉल्स एवं SMS द्वारा रिश्वतखोरी के प्रकरणों की जांच हेतु ACB में Digital Voice Logger की स्थापना की जायेगी।

- आम जनता को सगुम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में–
  - वैर–भरतपुर, डूंगरगढ़–बीकानेर, नैनवा–बूंदी, सरदारशहर–चूरू, अनूपगढ़–श्रीगंगानगर, नीमकाथाना–सीकर, जालौर, गंगापुरसिटी– सवाई माधोपुर, सिरोही, नसीराबाद–अजमेर, कठूमर–अलवर, लाडनूं–नागौर व सादुलशहर–श्रीगंगानगर में **अपर जिला एवं सैशन न्यायालय** खोले जायेंगे। साथ ही, थानागाजी–अलवर व कुचामन सिटी–नागौर में कैम्प कोर्ट खोले जायेंगे।
  - बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा व जोधपुर में **वाणिज्यिक न्यायालय** खोले जायेंगे।
  - गोगुन्दा–उदयपुर, बालेसर–जोधपुर, पीलीबंगा व रावतसर–हनुमानगढ़, दौसा, थानागाजी व मुण्डावर–अलवर, छबड़ा–बारां, खाजूवाला–बीकानेर व हिण्डौली–बूंदी में **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।
  - श्रीमाधोपुर–सीकर, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनूं, सोजत, समुरपुर–पाली व निवाई–टोंक में **अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।
  - गंगापुर–भीलवाड़ा, नोखा–बीकानेर, संगरिया–हनुमानगढ़ व लक्ष्मणगढ़–सीकर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोले जायेंगे।
  - पाली, राजसमंद व अलवर में **विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय** खोले जायेंगे।

सुशासन

अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्येय आमजन की सेवा करते हुए संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देना है। राज्य के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक हम सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। सुशासन के कुछ लक्ष्य कई बार असंभव–से लगते हैं, मगर जब पूरे मनोयोग से हम कोशिश करते हैं, तो वो असंभव भी संभव बन जाता है। मुझे स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां याद आ रही हैं–

'संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है,
असंभव से भी आगे निकल जाना।'

- सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों एवं टारगेट ग्रुप तक सहजता, सुगमता व समय से पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं **Social & Performance Audit Authority** के गठन की घोषणा करता हूं।
- प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु–
  - नीमकाथाना–सीकर में एडीएम कार्यालय, नेछवा–सीकर, नारायणपुर (बानसूर)–अलवर, रतनगढ़–चूरू, लवाण–दौसा में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित हैं। साथ ही, तहसील गोविंदगढ़–अलवर को उपखण्ड कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जायेगा।
  - श्री महावीरजी (हिण्डौन)–करौली, आऊ (लोहावट)–जोधपुर, टपूकड़ा (तिजारा), नौगावा (रामगढ़)–अलवर, कल्याणपुर (पचपदरा)–बाड़मेर, नगरफोर्ट (उनियारा)–टोंक, मित्रपुरा (बामनवास)–सवाई माधोपुर, बहरावण्डा (सिकराय), बैजुपाड़ा, सैंथल (महुवा)–दौसा, बस्सी–चित्तौड़गढ़, माधोराजपुरा (चाकसू), आंधी–जयपुर व गुढ़ागौड़जी (उदयपुरवाटी)–झुंझुनूं की उप तहसीलों को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाना व जोबनेर–जयपुर, दोवड़ा–आसपुर व बाड़मेर (ग्रामीण) में नवीन तहसील खोला जाना प्रस्तावित है।
  - फेफना (नोहर)–हनुमानगढ़, आनंदपुर कालू (जैतारण)–पाली, किशनगढ़–अजमेर, बिचून (दूदू)–जयपुर, गुढ़ा कटला (बांदीकुई), पापड़दा (सिकराय), कुण्डल–दौसा, साहवा (तारानगर), कातर छोटी–चूरू, बनकोड़ा (आसपुर), ओबरी (सागवाड़ा)–डूंगरपुर, कोयला (अंता)–बारां, दूदवा (पचपदरा)–बाड़मेर, रींगस–सीकर, जावदा (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, गंडाला (बहरोड़)–अलवर, चितावा–नागौर, गुढ़ा चन्द्र (टोड़ाभीम)–करौली, रायथल–बूंदी तथा दिवेर (भीम–देवगढ़)–राजसमंद में नयी उप तहसील खोली जायेंगी।
- प्रदेश में कोटकासिम–अलवर, बोरावड़–नागौर, धरियावाद–प्रतापगढ़, गोविंदगढ़, बरड़ौद–अलवर व ऋषभदेव–उदयपुर को नगर पालिका बनाया जायेगा।
- विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेज

व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकार प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिया जायेगा।

- राजस्थान का भामाशाह स्टेट डाटा सेन्टर देश का अग्रणी, Tier-IV Standard का डाटा सेन्टर है। इसके माध्यम से राज्य व अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों तथा निकायों के साथ-साथ स्टार्टअप्स एवं निजी क्षेत्र को भी आईटी की सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। हमें विश्वास है कि देश में डाटा सेन्टर की सेवाओं से राजस्व प्राप्त करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ-साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए Lateral Entry से सरकारी सेवा में आने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इससे लगभग 5 हजार भूतपूर्व सैनिकों को लाभांवित किया जायेगा।
- हमारे पिछले कार्यकाल में **प्रशासन गांवों के संग** तथा **शहरों के संग अभियान** बहुत कामयाब रहे हैं। शहरों के संग अभियान में पांच लाख पट्टे भी बांटे गये थे। अत: आगामी वर्ष में, नियमों का सरलीकरण कर 1 मई, 2021 से **'प्रशासन गांवों के संग'** तथा 2 अक्टूबर, 2021 से **'प्रशासन शहरों के संग'** अभियान चलाये जायेंगे।
- राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं, 3 हजार करोड़ रुपये की राशि से **कार्मिक कल्याण कोष** के गठन की घोषणा करता हूं।
- कोविड़-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि **Bar Council of Rajasthan** को सहायता प्रदत्त करने की घोषणा करता हूं।
- **Central Government Health Scheme (CGHS)** के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को Cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **CGHS** की तर्ज पर **Rajasthan Government Health Scheme (RGHS)** लागू करने की मैं, घोषणा करता हूं।
- राज्य कर्मचारियों के लिए लागू **समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना** में देय राशि 3 लाख रूपये के वर्तमान विकल्प के साथ-साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार, 10 लाख, 20 लाख एवं 30 लाख रुपये का विकल्प भी दिया जाना प्रस्तावित है।
- कोविड-19 से उपजी विषम आर्थिक स्थितियों से निबटने में हमें प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने अपने वेतन के एक अंश का सहयोग राशि के रूप में योगदान दिया। अब मैं, सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त करते हुए, उनके कोरोना के कारण डेफर किये गये वेतन, लगभग 1 हजार 600 करोड़ रुपये को Release करने की घोषणा करता हूं।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदाकर्मियों की समस्याओं के समाधान व उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अलग से सेवा नियम बनाने की घोषणा करता हूं। इससे संविदाकर्मियों का विभागवार Cadre बनाया जायेगा।
- राज्य के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान- **HCM RIPA, जयपुर** में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सिविल सोसायटी एवं

आमजन की Capacity Building हेतु प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करते हुए 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जायेगा।

- विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रियाओं में जटिलता होने के कारण आमजन, जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी–अधिकारियों को देय लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाते। अत: इस प्रक्रिया का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेज की अनिवार्यता समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval जैसे प्रावधान किये जायेंगे।
- हमारी गत सरकार के समय तथा गत दो वर्षों में प्रस्तुत किये गये बजट से आम जनता के साथ–साथ जनप्रतिनिधिगण में भी आशा का संचार हुआ है। इस कारण कई माननीय विधायकगण के माध्यम से मुझे उनके क्षेत्रों में कई छोटे किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्य कराने, संस्थाओं को खोलने व अपग्रेड कराने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं यथा आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नये विषय व संकाय, नये जीएसएस, नये उप स्वास्थ्य केन्द्र–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र, पुलिस चौकी आदि। यद्यपि ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए नाम व स्थान से बजट में प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है। किन्तु, मैं यहां आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसे कार्यों को करने के लिए आवश्यकतानुसार समुचित प्रावधान करते हुए, संबंधित विभागों को यथोचित निर्देश दिये जाते रहेंगे।
- अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से हमने प्रदेश के हर क्षेत्र, हर उम्र, हर वर्ग की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमने बजट में जो भी योजनायें प्रस्तावित की हैं, उनको समयबद्ध रूप से कुशलतापूर्वक लागू किया जायेगा ताकि हम अपने प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले जा सकें। मैं, सभी माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि, उन्नति के इस सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है–

'मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है
ये तो दौड़ भर थी अभी उड़ान बाकी है,
मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना
ये तो शुरुआत भर थी अंजाम अभी बाकी है।'

कर प्रस्ताव

- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।
- राज्य में कई अलाभकारी सामाजिक संस्थायें, मानवीय एवं सर्वधर्म सद्भाव की भावना से विशेष योग्यजन, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, भिक्षावृत्ति में संलिप्त एवं नशे से पीड़ित परिवारों की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार के सराहनीय कार्य कर रही हैं।
- ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिये Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) की तर्ज पर **सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (Social Security Investment Promotion Scheme: SSIPS-2021)** लागू करने की घोषणा करता हूं।
- इस योजना में SGST का पुनर्भरण, Motor Vehicle Tax, स्टाम्प ड्यूटी, लीज राशि, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, नियमन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट तथा ब्याज अनुदान दिया जायेगा इसमें बड़ी परियोजनाओं के लिये **Customized Package** का भी प्रावधान रहेगा।
- इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- जयपुर शहर में 50 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Revenue Research and Analysis** स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इसमें Commercial Taxes, Registration & Stamps Excise, Transport, Mines आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के लिये Analysis, Fraud Detection एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जायेगा। इसी भवन में State Directorate of Revenue Intelligence (SDRI) का कार्यालय भी स्थापित किया जायेगा।
- कर चोरी की सूचना देने पर SDRI में **'मुखबिर प्रोत्साहन योजना'** संचालित है। इसे Commercial Taxes, Registration & Stamps, Excise Transport Mines आदि विभागों में भी लागू किया जाकर नकद प्रोत्साहन राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये अधिकतम किया जायेगा।

- राजस्व अर्जन विभागों में महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाएं यथा पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी का Refund विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के Tax Clearance Certificate एवं Permit आदि का सरलीकरण किया जाकर Online किया जायेगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- हम आमजन की सुविधा के लिये पंजीयन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनायेंगे। इस दृष्टि से मैं चरणबद्ध रूप से **"Anywhere-Online Registration"** प्रणाली लागू करने की घोषणा करता हूं। इससे आमजन को पंजीयन कार्यालय जाने की बाध्यता समाप्त हो जायेगी। इस क्रम में DLC दरों का Technology के माध्यम से निर्धारण किया जाकर Geo-tagging के साथ Online किया जायेगा। साथ ही, यह तकनीक GIS के साथ नगरीय विकास कर (UD Tax) व्यवस्था में भी लागू की जायेगी।
- कोविड–19 से प्रभावित रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिये आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमियों की DLC दर 10 प्रतिशत कम करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही रिसोर्ट, खनन, मोबाइल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की DLC दरों को भी तर्कसंगत किया जायेगा।
- शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिये बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक की कीमत के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी को 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिये 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।
- Affordable Housing हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी EWS के लिये 1 प्रतिशत तथा LIG के लिये 2 प्रतिशत है। इसे घटाकर क्रमश: 0.50 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत किया जायेगा। यह लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा।
- आमजन को स्टाम्प ड्यूटी में राहत देते हुए, मैं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी सम्पत्ति के बाजार मूल्य (DLC) के बजाय आवंटन (Allotment) राशि पर लेना प्रस्तावित करता हूं।
- स्थानीय निकायों से पट्टा लेने से पहले ऐसी भूमि के संबंध में, 14 जुलाई, 2014 के बाद निष्पादित अंपजीकृत दस्तावेज (मध्यवर्ती) पर स्टाम्प ड्यूटी भूमि के बाजार मूल्य (DLC) के स्थान पर DLC के 40 प्रतिशत पर लिया जाना प्रस्तावित है।
- रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिये विक्रय इकरारनामों (Agreement to sale) पर प्रदत्त स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जायेगा।
- पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत माता–पिता, भाई–बहन, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री, बुआ–भतीजा, मामा–भांजा, मामा–भांजी तथा पति–पत्नी को ही उपलब्ध है। यह लाभ अविभाजित पैतृक सम्पत्ति के सभी सह–हिस्सेदारों और उनके उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।
- पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत व अधिकतम 1 लाख रुपये है जबकि पुत्रवधुओं के लिये स्टाम्प ड्यूटी 2.5 प्रतिशत है। पुत्रवधुओं को भी पुत्रियों के समान ही रियायत दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, मैं पोता–पोती, दोहिता–दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णरूप से मुक्त करने की घोषणा करता हूं।
- प्रतिभूति बंध–पत्र (Security Bond) पद देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये करना प्रस्तावित है। साथ ही ऋण दस्तावेज पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी के पुराने मामलों का निपटारा करने के लिये 1 अप्रेल, 2021 से एक नई Amnesty Scheme लायी जायेगी।
- स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई–पंजीयन योजना के अनुरूप करने तथा स्टाम्प वेन्डर्स की सहभागिता

बढ़ाने के लिये ई–स्टाम्प पर कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टाम्प पत्रों के समान किया जायेगा।

- प्रदेश में Public-Private Partnership परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिये Concession Agreement की परिभाषा को संशोधित कर इसकी परिधि में केन्द्र सरकार एवं उसके उपक्रमों एवं निकायों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आदि से LLP (Limited Liability Partnership) में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 0.50 प्रतिशत देय है। LLP से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर भी समान स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी।
- कोविड–19 के दौरान 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर देय Land Tax पर ब्याज एवं शास्ति में 1 मई 2020 से 30 जून, 2020 की अवधि में छूट दी गई थी। इस रियायत को 30 जून, 2021 तक बढ़ाना प्रस्तावित करता हूं।

उद्योग विभाग

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 (RIPS-2014) नें 4,900 इकाइयों द्वारा 1.16 लाख करोड़ रुपये का निवेश तथा 1.96 लाख रोजगार सृजन हुआ था। जबकि एक वर्ष की न्यून अवधि में RIPS-2019 ने अब तक 2,789 इकाइयों द्वारा 0.69 लाख करोड़ रुपये का निवेश तथा 69,750 लोगों को रोजगार मिला है।
- यह नई RIPS-2019 योजना राज्य के निवेशकों के लिये वरदान साबित हो रही है, इसे और प्रभावी एवं व्यापक बनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत–

(i) RIPS-2019 नें ''डॉ. बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज'' के अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे–

- Investment Limit 50 प्रतिशत घटाई जायेगी
- अधिकतम अनुदान को EFCI (Eligible Fixed Capital Investment) के 150 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया जायेगा
- 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक अथवा 15 प्रतिशत Capital Subsidy अधिकतम 2 करोड़ रुपये दी जायेगी।
- SC/ST उद्यमियों के लिय विशेष Incubation Centres चलाये जायेंगे।
- इस पैकेज हेतु SC/ST उद्यमियों का Proprietorship Firm में शत प्रतिशत तथा Partnership Firm एवं Private Limited Company में न्यूनतम 51 प्रतिशत पूंजी निवेश होना आवश्यक है।

(ii) Most Backward, Backward एवं Tribal Areas में निवेश करने पर RIPS-2019 के तहत सभी को ''डॉ.बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज'' की भांति लाभ दिये जायेंगे।

(iii) Gems & Jewellery राजस्थान का परम्परागत उद्योग है एवं इसमें रोजगार की विपुल सम्भावना है। अत: इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये राज्य में Gems & Jwewllery Bourse को RIPS-2019 के सेवा क्षेत्र में जोड़ने की घोषणा करता हूं।

(iv) कोविड–19 के दौरान राज्य में Healthcare Sector में सराहनीय कार्य हुआ है। साथ ही वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में Healthcare Sector में निवेश के साथ–साथ Active Pharmaceutical Ingredients (API) उद्योग लगने की भी आवश्यकता एवं सम्भावना है। अत: Healthcare Sector एवं API को RIPS-2019 के Thurst Sector में जोड़कर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(v) रिसोर्टस एवं एम्यूजमेन्ट पार्क (Resorts and Amusement Park) के लिए RIPS-2019 के अन्तर्गत न्यूनतम भूमि की शर्त क्रमश: 5 एकड़ एवं 10 एकड़ है, जिसे कम करते हुये Building Bye Laws के अनुरूप रिसोर्ट के लिये 2 एकड़ एवं Amusement Park के लिये 2.5 एकड़ करने की घोषणा करता हूं।

(vi) सोलर एवं विंड ऊर्जा की राज्य में विपुल सम्भावना है। इन सेक्टर्स की Equipment Manufacturing इकाइयों को RIPS-2019 के अन्तर्गत रोजगार अनुदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

(vii) RIPS-2019 के क्लाज 11.4 (ii) में Plant & Machinery and Equipments के साथ–साथ Development of Infrastructure जोड़कर उस पर भी ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

(viii) राज्य में e-Vehicles को प्रोत्साहन देने के लिये–

- e-Charging and Swapping Stations को RIPS-2019 के Service Sector में जोड़ कर Thrust Sector के लाभ दिये जायेंगे।
- विशेष रूप से e-Vehicles उत्पादन के लिये निवेश सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ रुपये किया जायेगा।

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2014 की कार्य अवधि (Operative Period) 31 मार्च, 2021 तक ही है। कुछ इकाइयां योजना अवधि में उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पायी है। जिन्हें लाभान्वित करने के लिये RIPS-2014 की कार्यावधि को दो वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक किये जाने की घोषणा करता हूं।

परिवहन विभाग

- वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Transport Amnesty Scheme-2021 लागू किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2021 तक होगी, इसमें–

(i) मोटर वाहनों पर 31 जनवरी, 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(ii) ई–रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी, 2021 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि (Compounding Fee) पर 75 प्रतिशत से लेकर लगभग 95 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।

(iii) बकाया राशि जमा होने पर, नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन तिथि के बाद का कर, ब्याज एवं शास्ति माफ किया जाना प्रस्तावित है।

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वर्तमान प्रशमन राशि (Compounding Fee) को कतिपय Traffic Offences के लिये कम किया जाना प्रस्तावित है, जैसे–
  - ओवरलोडिंग – 20 हजार से 5 हजार रुपये
  - वजन कराने से इंकार – 40 हजार से 10 हजार रुपये।
  - सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

इस प्रकार प्रशमन राशि (Compounding Fee) कम किये जाने का लाभ पूर्व में कारित Traffic Offences के संबंध में भी प्राप्त होगा।

- स्टेज कैरिज के अन्य श्रेणी मार्गों के लिये देय Motor Vehicle Tax की दूरी आधारित (150 कि.मी., 300 कि.मी. तथा 300 कि.मी. से अधिक) प्रतिदिन संचालन की तीन श्रेणियां हैं। इसे युक्तिसंगत बनाने तथा Transporters को राहत देते हुये न्यूनतम 100 कि.मी. के बाद 50–50 कि.मी. के 8 स्लेब बनाकर प्रोग्रेसिव Moter Vehicle Tax लगाया जाना प्रस्तावित करता हूं।
- डम्पर श्रेणी के भार वाहनों पर देय Moter Vehicle tax को 1800 रुपये प्रति टन या इसके भाग के लिये अधिकतम 35 हजार रुपये वार्षिक प्रति वाहन निर्धारित किया जाना प्रस्तावित करता हूं।
- 32 से अधिक सीट वाली ऑल राजस्थान संविदा परमिटधारी बसों के लिये देय मासिक Moter Vehicle tax को 775 रुपये प्रतिसीट प्रतिमाह से घटाकर 700 रुपये (अधिकतम 40 हजार रुपये) किया जाना प्रस्तावित है।

एक नई पहल करते हुए इसी श्रेणी की बसों के लिये संभागीय क्षेत्र के परमिट लेने पर Moter Vehicle tax में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना प्रस्तावित करता हूं।

- मैंने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नई पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को विशेष पथ कर में शत–प्रतिशत छूट दी थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन सम्भव हुआ एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई थी। उसी के अनुरूप, इन मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर मैं फिर से Moter Vehicle tax में तीन वर्ष तक शत–प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।
- स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज की नयी पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिये पंजीयन तिथि से 15 दिवस तक **Moter Vehicle tax** की देय राशि में पूर्ण छूट देना प्रस्तावित करता हूं।
- वाहन का उपयोग नहीं होने से, पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) सरेंडर करने की न्यूनतम अवधि, स्टेज कैरिज के अलावा अन्य वाहनों हेतु एक कैलेंडर माह है। इसे व्यावहारिक बनाते हुए 30 दिवस किया जायेगा। सभी श्रेणी के वाहनों की RC सरेंडर करने की अधिकतम अवधि 90 दिवस निर्धारित की जायेगी।
- कोविड–19 के कारण बसें संचालित नहीं होने से Tour Operators को हानि हुई है। अत: Indian Association of Tour Operators (IATO) और Rajasthan

Association of Tour Operators (RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक Monthly Motor Vehicle Tax में पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूं।

- सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वाहनों की ओवरलोडिंग से जनहानि के साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये परिवहन विभाग के उड़नदस्तों (Flying Squads) को Portable Weighing Machine उपलब्ध कराई जायेगी।
- कोविड–19 से प्रभावित मध्यमवर्ग को राहत देने के लिये पुराने वाहनों (Used Vehicles) के स्वामित्व हस्तान्तरण पर देय अतिरिक्त कर (Additional One Time Tax) में दुपहिया वाहन एवं कारों के लिये 31 मार्च, 2022 तक 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा करता हूं।
- मैंने 2019–20 के बजट में 'इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति' लाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार सभी प्रकार के e-Vehicles के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये 31 मार्च 2022 तक–

(i) इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किया जाएगा।

(ii) e-Vehicles राज्य में Moter Vehicle Tax से मुक्त है। इन वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु अलग–अलग श्रेणी अनुसार एकमुश्त अनुदान देने की घोषणा करता हूं।

- Two Wheelers : बैटरी क्षमतानुसार 5 हजार से 10 हजार रुपये प्रति वाहन
- Three Wheelers : बैटरी क्षमतानुसार 10 हजार से 20 हजार रुपये प्रति वाहन

खान एवं भू विज्ञान विभाग

- प्रदेश में अप्रधान खनिजों (Minor Minerals) की खोज की गति बढ़ाने हेतु निजी उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इस दृष्टि से उद्यमियों को Non-Exclusive Prospecting Licences (NEPL) दिया जाना प्रस्तावित है। NEPL धारक द्वारा बनाई गई पूर्वेक्षण रिपोर्ट (Prospecting Report) के आधार पर विभाग द्वारा नीलामी करके खनन पट्टे दिये जायेंगे।
- निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

आबकारी विभाग

- हथकढ़ शराब के प्रचलन तथा पड़ोसी राज्यों से आनी वाली अवैध शराब को रोकने के लिये सीमावर्ती जिलों में आबकारी थानों व चौकियों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करके उनका पुनर्वास करने हेतु हमने वर्ष 2009 में ''नवजीवन योजना'' प्रारम्भ की थी। इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

इसे व्यापक बनाते हुये ऐसे परिवारों की नशामुक्ति, पुनर्वास, उनके बच्चों की शिक्षा, तथा उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिये प्रेरित करने हेतु एक विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी। इस हेतु मैं, 100 करोड़ रुपये से **''नवजीवन कोष''** के गठन की घोषणा करता हूं।

- राज्य में शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर पूर्व विधायक श्री गुरूशरण छाबड़ा के साथ 8 सितम्बर, 2013 को हुये समझौते की पालना के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्यसंयम हेतु ''स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान'' चलाया जायेगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

कृषि विपणन

- हमारी सरकार किसानों की सदैव हितैषी रही है। इस दृष्टि से, मैं 1 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये, वर्तमान में देय मण्डी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं **आढ़त** के संबंध में घोषणा करता हूं कि –

(i) गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी एवं देशी घी पर मण्डी शुल्क 1.60 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत,

(ii) अन्य कृषि जिन्सों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर मण्डी शुल्क 1.60 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा तिलहन पर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत,

(iii) कृषक कल्याण शुल्क को तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देशी घी एवं अन्य कृषि जिन्सों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत एवं फल–सब्जी पर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत,

(iv) फल–सब्जी पर आढ़त 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत एवं तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देशी घी व अन्य कृषि जिन्सों पर आढ़त 2.25 प्रतिशत से घटाकर 1.75 प्रतिशत की जायेगी।

उपनिवेशन विभाग

- हमारी सरकार किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। उपनिवेशन क्षेत्र (Colonisation Area) के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर 1 अप्रेल, 2021 से 30 जून, 2021 की अवधि में–

(i) 30 जून, 2021 तक की शेष रही बकाया किश्ते एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत् प्रतिशत छूट

(ii) आवंटन की समस्त बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में शत् प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित करता हूं।

वाणिज्यिक कर विभाग

- त्रुटिपूर्ण Declaration Forms को संशोधित करने तथा बकाया Declaration Forms को प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के कारण व्यवहारियों को समस्या आ रही है। अत: इनकी अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही VAT-40E विवरणी पेश करने की समयावधि को 30 जून, 2021 तक बढ़ाकर ठेकेदारों को राहत देना प्रस्तावित करता हूं।
- वर्तमान में राज्य में 50 हजार रुपये व अधिक के माल के परिवहन हेतु **e-way bill** जारी करना अनिवार्य है। छोटे व्यापारियों को हो रही असुविधा को ध्यान रखते हुये e-way bill जारी करने की सीमा को बढ़ाकर **1 लाख रुपये** किये जाने की घोषणा करता हूं।
- GST लागू होने के बाद Repealed Acts यथा Sales Tax, Vat, Entry Tax, Entertainment tax एवं Luxury Tax से संबंधित मांग, विभाग के साथ Disputes एवं न्यायालयों में अनेक प्रकरण लम्बित होने से व्यवहारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि, Covid-19 से उद्योग एवं व्यापार जगत पर पड़े विपरीत प्रभाव के मध्यनजर एक सरल, व्यापक एवं एकीकृत **Amnesty Scheme -2021** तुरन्त प्रभाव से लागू की जायेगी। जिसमें **पहली बार मूल Tax में भी** छूट देना प्रस्तावित है।
- इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यवहारियों को लाभ देने हेतु कर निर्धारण के ex-party आदेशों को Re-open करने एवं Rectification हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाया जायेगा।
- इस स्कीम के अन्तर्गत कोई **Monetary Ceiling** नहीं होगी। इसमें ब्याज एवं शास्ति में पूर्ण छूट के साथ मूल Tax में भी श्रेणी वाइज छूट होगी। जो पहले विकल्प देगा उसे अधिक छूट मिलेगी। यह स्कीम पूर्णतया **Online एवं Faceless** होगी तथा 30 सितम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगी।
- मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को Hardship हुई है। अत: **उपरोक्त कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि इस कोरोना–काल में लगभग 910 करोड़ रुपये से अधिक की राहत** प्रदान की जा रही है।
- इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।
- इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

संशोधित अनुमान वर्ष 2020–21 एवं बजट अनुमान वर्ष 2021–22

- अब मैं, वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है–

राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 47 हजार 980 करोड़ 19 लाख रूपये
राजस्व व्यय 1 लाख 89 हजार 701 करोड़ 80 लाख रूपये
राजस्व घाटा 41 हजार 721 करोड़ 61 लाख रूपये
पूंजी खाते में प्राप्तियां 1 लाख 172 करोड़ 39 लाख रूपये
पूंजी खाते में व्यय 58 हजार 360 करोड़ 82 लाख रूपये
पूंजी खाते में आधिक्य 41 हजार 811 करोड़ 57 लाख रूपये

वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

- राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ 13 लाख रूपये
  राजस्व व्यय 2 लाख 8 हजार 80 करोड़ 17 लाख रूपये

राजस्व घाटा 23 हजार 750 करोड़ 4 लाख रूपये

पूंजी खाते में प्राप्तियां 66 हजार 501 करोड़ 90 लाख रूपये

पूंजी खाते में व्यय 42 हजार 667 करोड़ 16 लाख रूपये

पूंजी खाते में आधिक्य 23 हजार 834 करोड़ 74 लाख रूपये

राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

- कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में आयी गिरावट को देखते हुए राजस्व प्राप्तियों में आगामी वर्ष में भी पर्याप्त वृद्धि संभावित नहीं है। अत: सरकार के कार्यकलापों के संचालन व लोक कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने की दृष्टि से वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों में राशि रुपये 23 हजार 750 करोड़ 4 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

- पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अभिशंसा के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलु उत्पाद (GSDP) की 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। इसी सीमा में वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि रुपये 47 हजार 652 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.98 प्रतिशत है।
- मैं सदन का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा देय केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में की गई कटौती की ओर दिलाना चाहूंगा। वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश को प्राप्त होने वाली राशि में केन्द्र द्वारा रुपये 14 हजार करोड़ 94 लाख की कमी की गयी। साथ ही, आगामी वर्ष हेतु भी मात्र रुपये 40 हजार 106 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2020–21 के प्रारंभिक अनुमान से भी रुपये 6 हजार 779 करोड़ 36 लाख कम है। हमारे द्वारा इस कमी की पूर्ति करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त ऋण सीमा का उपयोग करने के साथ–साथ वित्तीय प्रबंधन पर फोकस किया गया।
- हमारे द्वारा कुशल वित्तीय प्रबंधन किया जाकर प्रदेश के सभी तबकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की कार्य योजना बनाते हुए, एक दूरगामी विजन के साथ बजट तैयार किया गया है।
- मैं, वर्ष 2021–22 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूं। साथ ही, FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत

वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement) भी सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

- वर्ष 2021–22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट–पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही है।
- मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम, पक्ष व प्रतिपक्ष, कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे–

'निगाहों में मंजिल थी
गिरे और गिरकर संभलते रहे,
हवाओं ने बहुत कोशिश की
मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।'

इन्ही भावनाओं के साथ मैं, बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द

बजट 2021-22 बहस पर जवाब में

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणाएं

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं, घोषणा करता हूं कि –
  - एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान से वंचित–बांसड़ी कला व प्रेमसिंहपुरा (दांतारामगढ़)–सीकर सहित 784 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
  - दुहार, चौगान (थानागाजी), बीघोता (राजगढ़), चतरपुरा (बानसूर)–अलवर, संगतपुरा, मन्नीवाली (सादुलशहर)–श्रीगंगानगर, घाटमीका (कामां)–भरतपुर, सिंघाना (डीडवाना)–नागौर, नैनों की ढाणी, नांदड़ी (मण्डोर), घंटियाली–जोधपुर, गोविंदपुरा (खंडेला)–सीकर, चौरू (उनियारा)–टोंक, चांचोड़ी (सुमेरपुर)–पाली एवं मेहराना (भादरा)–हनुमानगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
  - नाथद्वारा–राजसमंद में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा।
  - जाणुन्दा, जावड़ (मारवाड़ जंक्शन)–पाली, बाड़ी–जोड़ी (विराटनगर)–जयपुर, फरडौद (जायल)–नागौर, चाबा (शेरगढ़)–जोधपुर, तिगांवा (कोटकासिम)–अलवर, खरैरी (वैर)–भरतपुर तथा खुड़ी बड़ी (लक्ष्मणगढ़)–सीकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।
  - जजावर (नैनवां)–बूंदी, भियाड़ (शिव), चवा–बाड़मेर, जलूथर (नगर), सिनसिनी–भरतपुर, बलारा (लक्ष्मणगढ़)–सीकर, मानपुर (सिकराय), आभानेरी (बांदीकुई), नांगल राजावतान–दौसा, केरू (लूणी), तेना (शेरगढ़)–जोधपुर, 61 एफ ब्लॉक श्रीकरणपुर, बींझबायला ब्लॉक पदमपुर–श्रीगंगानगर, झिझिनियाली–जैसलमेर, रेनवाल मांझी व माधोराजपुरा – जयपुर, रेवतड़ा–जालेर व बड़ोदिया (बागीदौरा)–बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
  - किशनपोल–जयपुर में सेटेलाइट अस्पताल बनाया जायेगा।
  - लालसोट–दौसा, बस्सी, जमवारामगढ़ व फागी–जयपुर एवं लक्ष्मणगढ़–सीकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
  - उप जिला चिकित्सालय सलूंबर–उदयपुर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
  - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुर (शाहपुरा)–जयपुर में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 व अरांई (किशनगढ़)–अजमेर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 तथा जिला चिकित्सालय–धौलपुर की बेड क्षमता में 100 बेड की वृद्धि की जायेगी।
  - बगड़िया अस्पताल (सुजानगढ़)–चूरू में आईसीयू विकसित किया जायेगा।
  - कुम्हेर–भरतपुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी।
  - जोधपुर के मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल में Trauma Center की सुविधा बढ़ाने के लिए Neuro Surgery की एक और Unit तथा महात्मा गांधी अस्पताल में Ortho Spine Unit खोली जायेगी।

शिक्षा

- कृषि संकाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा की गयी है। इसी क्रम में, अब माननीय सदस्यों ने विज्ञान संकाय खोलने के लिए ज्ञापन दिये हैं, उनकी भावना के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर English Medium के 200 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाना प्रस्तावित है।

- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सेवा की ढाणी (शाहपुरा)–जयपुर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने एवं आधारभूत सुविधायें विकसित करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने एवं युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्य विषय के साथ–साथ अन्य विषयों के Selected Course का विकल्प लिए जाने की व्यवस्था आवश्यक है। जैसे किसी आर्किटेक्ट का कोर्स करने वाले अथवा Music में डिग्री करने वालों को इनसे संबंधित Updated कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार Artificial Intelligence पर काम करने वाले युवाओं को Behavioural Sciences का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार Mixed Subjects के साथ में अध्ययन करने की व्यवस्था को Credit Based प्रणाली कहते हैं। आगामी वर्ष से चरणबद्ध रूप से प्रदेश में उच्च शिक्षा में Credit Basesd प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के Autonomous Engineering Colleges की शैक्षिक गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारां व भीलवाड़ा Engineering Colleges को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा तथा अजमेर, बीकानेर व महिला अजमेर Engineering Colleges को तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का बांसवाड़ा स्थित Engineering College को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का एवं बाड़मेर Engineering College को प्रस्तावित MBM विश्वविद्यालय, जोधपुर का संघटक (Constituent) कॉलेज बनाते हुए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही, बाड़मेर Engineering College में पेट्रोलियम संकाय खोला जायेगा।
- डीडवाना–नागौर में कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा।

खेल :

- डीग व कुम्हेर–भरतपुर में खेल स्टेडियम बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

कृषि :

- किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने, तत्काल मंडी उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ता तक सीधी सप्लाई सुनिश्चित किये जाने के लिए मैं, **किसान ई–मंडी** की स्थापना की घोषणा करता हूं।
- किसानों को जैविक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर व कोटा में **Rajasthan State Seed & Organic Certification Agency** के उपकेन्द्र खोले जायेंगे। साथ ही, एकल कृषकों को जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट दिया जाना भी प्रस्तावित है।
- मंडावा–झुंझुनूं, भुसावर (वैर)–भरतपुर, चांदगोठी (सादुलपुर)–चूरू व बायतू–बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- बामनवास–सवाई माधोपुर, रैणी–अलवर में कृषि उपज मण्डी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, खण्डार–सवाई माधोपुर में फल–सब्जी मण्डी खोली जायेगी।

पशुपालन :

- 600 पशु चिकित्सा उप–केन्द्रों में 3 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेंगी।
- जैसलमेर जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा :

- बेघर व्यक्तियों को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पुनर्वास हेतु **बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति–2021** लायी जायेगी।
- वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं को प्रगति के उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाये जाने के लिए 20 करोड़ रुपये राशि का **वाल्मीकि कोष** बनाये जाने की घोषणा करता हूं।
- राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र–छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जायेगी तथा जिनके माता–पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल–11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

अल्पसंख्यक मामलात :

- प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं Merit-cum-means छात्रवृत्ति योजना से वंचित रहे, पात्र अभ्यर्थियों को भी

छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य के विद्यालयों, जिनमें कक्षा 6 से 8 में 10 से अधिक विद्यार्थी अल्पसंख्यक भाषा में अध्ययन के इच्छुक होंगे, उन विद्यालयों में अल्पसंख्यक तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/सिंधी/ गुजराती/पंजाबी) के अतिरिक्त शिक्षक लगाये जायेंगे।
- नगर–भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास एवं गडरारोड (शिव)–बाड़मेर में अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जायेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

- राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3–4 गुणा बढ़ाकर 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित है।
- कुसुम योजना के अन्तर्गत TSP क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने हेतु सागवाड़ा–डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से **वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र** का निर्माण करवाया जायेगा।

उद्योग :

- खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष में 5500 कत्तिनों एवं 300 बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। साथ ही, प्रशिक्षण अवधि में कत्तिनों एवं बुनकरों को क्रमश: 300 एवं 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जायेगा। इनमें से 500 कत्तिनों को अम्बर चर्खे तथा 300 बुनकरों को लूम वितरित किये जायेंगे। 10 हजार कत्तिनों एवं बुनकरों को **इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना** में ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जायेगी।
- Electronic एवं अन्य Toys तथा Sports Goods को विदेश से आयात करने के बजाय राज्य में ही बनाने की प्रबल संभावना है। अत: इन क्षेत्रों को RIPS-2019 के Thrust Sector में सम्मिलित किया जायेगा।
- RIPS-2019 के अंतर्गत Plug and Play Office Complex में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पात्र निवेश को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपये किया जायेगा।
- RIPS-2019 के अंतर्गत वर्तमान में पर्यटन एवं स्टार्ट–अप की MSME ईकाइयों को ही जिला स्तर पर आवेदन करने का प्रावधान है। अब यह सुविधा समस्त Service Sector की MSME इकाइयों को दी जायेगी।
- राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु वर्ष 2013–14 से पूर्व के ऋणों के लिए **एमनेस्टी योजना** लायी जायेगी, जिसमें ऋणों के एकमुश्त भुगतान पर दण्डनीय ब्याज व सामान्य ब्याज माफी के साथ मूल राशि पर भी छूट दी जायेगी। इसी क्रम में निगम को 20 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान भी दिया जायेगा। साथ ही, SC, ST, OBC, Minortiy Corporations को सुदृढ़ किया जायेगा।
- तूंगा (बस्सी)–जयपुर, जावाल–सिरोही एवं खेड़ली (कठूमर)– अलवर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे।
- Bhiwadi Industrial क्षेत्र एवं Marwar Industrial एरिया के अनुरूप औद्योगिकीकरण की संभावनाओं को देखते हुए, जयपुर–बस्सी–दौसा के मध्य उचित जगह पर दिल्ली–मुम्बई Express Way के निकट रीको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

श्रम एवं रोजगार :

- प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर स्किल टेस्टिंग व कॅरियर काउंसलिंग सेंटर्स स्थापित किये जायेंगे। जिससे उद्योगों की मांग के अनुरूप Trained एवं Skilled Manpower उपलब्ध हो सकेंगे।

नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय :

- राज्य की प्रत्येक नगरपालिका में एक, नगर परिषद में 3 एवं नगर निगम में 5 open जिम स्थानीय पार्कों में स्थापित किये जायेंगे। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय होना संभावित है।
- कोविड में लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020–21 में आर्थिक–सामाजिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। इस कारण वर्ष 2020–21 के लिए घोषित 5 हजार डेयरी बूथों में से लगभग 1 हजार 500 बूथ ही स्थापित हो पाये हैं। हम इस कार्य को आगामी वर्ष में पूर्ण करते हुए और आगे ले जायेंगे। इस प्रकार, आगामी वर्ष में 5 हजार डेयरी बूथों का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा।

- जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में सीवर लाइन व अन्य कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- सांगोद–कोटा में 2 करोड़ रुपये की लागत से River Front विकसित किया जायेगा।
- फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण करवाया जायेगा।

पेयजल/भूजल :

- बागीदौरा–बांसवाड़ा में झैर और जीवाखूटा एनिकट से पेयजल हेतु 2 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर तैयार करवायी जायेगी। साथ ही, हरिदेव जोशी केनाल में नवीन साईफन का निर्माण करवाया जायेगा।
- भादरा के 14, नोहर के 14 तथा तारानगर के 2 गांव, जो वर्तमान में बारानी हैं, इनको सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने की डीपीआर बनाने की घोषणा की गयी थी। यद्यपि इस क्षेत्र के लिए कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त Water Allowance नहीं इंगित किया गया है, किन्तु क्षेत्र की समस्या को देखते हुए पुनः Feasibility Report बनाया जाना प्रस्तावित है।
- सुरपुरा बांध–जोधपुर के डूब क्षेत्र में अधिक वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से चैनल निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।
- देवास तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर में पेयजल तथा मानसी वॉकल तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर एवं सिरोही जिले को पेयजल हेतु एवं जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु Feasibility Report बनायी जायेगी।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नेछवा (लक्ष्मणगढ़)–सीकर में A.En. Office एवं कामां–भरतपुर में Ex.En. Office खोले जायेंगे।

सार्वजनिक निर्माण :

- प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर व डामरीकरण के कार्य करवाये जायेंगे। जो इस प्रकार हैं–
  - समद का पार, गोरालिया फांटा से खड़ीन तक (शिव)–बाड़मेर की 30 किलोमीटर तक की सड़क का मेजर रिपेयर कार्य करवाया जायेगा।
  - टोड़ाभीम–करौली में 15 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास बनाया जायेगा।
  - बस्सी–जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग संख्या 2 (दौसा–तूंगा–चाकसू से नागौर) के 19 किलोमीटर रोड का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण किया जायेगा।
  - खजूरी (बिछीवाड़ा)–डूंगरपुर में रतनपुर से माखरेड़ा सड़क पर पुलिया मरम्मत तथा मालमाथा कालकी माता से काला पाणा गुजरात सीमा तक सड़क निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।
  - बैलवा राणा जी से सिद्धों का थान, बम्बोर से चांमू (शेरगढ़)– जोधपुर तक की सड़क का डामरीकरण किया जायेगा।
  - बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में सम्पर्क सड़क टाड़ावडला से उंकाला, कलिंजरा से वलुंडा वसुनी सीमा तक व मुंदड़ी हमीरपुरा से सूरजकुण्ड तक डामरीकरण, सड़क का निर्माण कार्य तथा सम्पर्क सड़क चनावाला पुल निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।
  - राज्य राजमार्ग-87A गोडू–बज्जू–कोलायात–मोखां खालसा में 50 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य करवाया जायेगा।
  - महंगी से दूधली मोड़ (एन.एच.21) वाया भावनी, भावनीखुर्द, सायपुर, आंधी, श्रीरामनगर, बिरासना, गांवली, नेवर, मकसुदनपुरा, चावण्डिया सड़क का निर्माण करवाया जायेगा।
- चम्बल नदी, सोने का गुर्जा (सेवरपाली) बाड़ी–धौलपुर पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
- माननीय विधायकगणों से सड़कों के निर्माण, रिपेयर व डामरीकरण आदि के बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते जा रहे हैं। इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को परीक्षण कर Estimate बनाने हेतु निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं।

ऊर्जा :

- हनुमानगढ़–गंगानगर जिले में प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 329 करोड़ रुपये की लागत से 400 KV ग्रिड सबस्टेशन हनुमानगढ़ में स्थापित किया जायेगा।
- भाडखा–हरियाली–बाड़मेर में 33 केवी का जीएसएस स्थापित किया जायेगा।
- प्रतापगढ़ (थानागाजी)–अलवर, रोल (जायल)–नागौर, हरसौली–अलवर व जमवारामगढ़–जयपुर में A.En. Office (विद्युत) खोले जायेंगे।

परिवहन :

- खाजूवाला–बीकानेर व कामां–भरतपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण :

- प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं इससे संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत **Environmental Management Cell (EMC)** का गठन किया जायेगा।
- प्रदेश में उद्योग, होटल, अस्पताल, खान आदि की स्थापना एवं संचालन हेतु Consent एवं Authorisation शीघ्र तथा सुगमता से उपलब्ध कराने की दृष्टि से सिरोही, राजसमंद, झुंझुनूं, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, नागौर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ व बूंदी जिलों में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल के 10 नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेंगे।
- राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु वृक्षारोपण तथा अग्रिम मृदा कार्यों के लिए आगामी 2 वर्षों में 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज :

- मनरेगा योजना के अकुशल श्रमिक परिवारों को अपने औजारों–गैंती, फावड़ा, तगारी आदि की मरम्मत के लिए प्रत्येक 50 दिनों का रोजगार पूरा करने पर आगामी वर्ष 50 रुपये की सहायता राशि दी जायेगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

पर्यटन :

- रामदेवरा–जैसलमेर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

कला एवं संस्कृति :

- राज्य की कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित व संरक्षित करने के उद्देश्य से जवाहर कला केन्द्र में विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

- Bio-technology व Public Health की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विषयों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि के अन्य विषयों के समान दर्जा दिया जायेगा।

राजस्व :

- बांदनवाड़ा–अजमेर व आगोलाई (बालेसर)–जोधपुर में उप तहसील कार्यालय खोला जायेगा। तूंगा (बस्सी)–जयपुर, सुहागपुरा, दलोट–प्रतापगढ़, कुराबड़ (गिर्वा), नयागांव (खैरवाड़ा)–उदयपुर, सम–जैसलमेर व नेछवा (लक्ष्मणगढ़)–सीकर की उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- सीकरी (नगर)–भरतपुर व भीण्डर–उदयपुर में उपखण्ड कार्यालय (SDO) खोले जायेंगे।
- शहीद स्मारक डाबला (डीडवाना)–नागौर के विकास हेतु 50 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

गृह :

- टोकर (सेमारी), सांगवाड़ा (बाबलवाड़ा) खैरवाड़ा–उदयपुर एवं मौथली चौराहा–डूंगरपुर में नवीन पुलिस चौकियां खोली जायेंगी। जयसिंहपुरा खोर–जयपुर में नया पुलिस थाना एवं सुजानगढ़–चूरू में सदर पुलिस थाना खोला जायेगा। साथ ही, पुलिस चौकी, डीग–भरतपुर को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाया जायेगा।

विधि :

- बस्सी–जयपुर व नवलगढ़–सीकर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ) खोले जायेंगे।
- टोड़ारायसिंह–टोंक के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (Sr. CJ & ACJM)** में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, लोहावट व बाप–जोधपुर, लखनपुर–भरतपुर एवं बीदासर–चूरू में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (CJJM) खोले जायेंगे।
- प्रदेश में आगामी वर्ष में 200 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त किया जायेगा। साथ ही, नोटेरी पब्लिक के 500 नये पद स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क :

- राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में देय मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करते हुए 'Universal Health Coverage' में शामिल किया जायेगा।
- वर्तमान में Senior Journalists के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। इस राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

ऐतिहासिक, साहसिक और सर्वांगीण विकास को समर्पित प्रदेश का बजट

चिकित्सा-स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार और कर-राहत पर केंद्रित

महेश चंद्र शर्मा

"मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट ऐतिहासिक, साहसिक, अभिनव-प्रयोगधर्मी कहा जा सकता है। इसकी आत्मा में प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, सेहत की सुरक्षा के प्रति जहां संवेदनशीलता की झलक दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर इसमें अनेक जन-कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया गया है। कोविड महामारी के दौरान प्रभावित लोगों की रोजी-रोटी, कारोबार व उद्योगों को संबल और कर राहत देने के लिए बजट में पूरी जवाबदेही का एहसास हो रहा है।"

निर्बाध प्रगति का संकल्प

बजट में युवाओं को रोजगार के नए अवसर जुटाने, बिना वर्ण, वर्ग और लिंगभेद के समाज के हर तबके के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने और प्रगति को निर्बाध बनाए रखने के संकल्प का एहसास भी होता है।

ऐतिहासिकता

बजट की ऐतिहासिकता, इसके पहली बार पेपरलेस होने, इसके वाचन में पौने तीन घंटे लगना और इसमें राज्य के विकास और आमजन के हितों से जुड़ी कुल 295 घोषणाओं को शामिल किया जाना रहा। सबसे महत्त्वपूर्ण घोषणा जो आम व्यक्ति की सेहत की सुरक्षा से सीधी जुड़ी-यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना वाली रही। इसमें सालाना महज 850 रुपए में प्रदेश के हर परिवार को, पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया है।

विश्वव्यापी कोविड महामारी के संकट के दौर से गुजर रहे प्रदेश में कोरोना प्रबंधन को प्रभावी बनाए रखने के लिए विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। राज्य को देश में चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के इरादे से इसके बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए राजस्थान मॉडल और पब्लिक हेल्थ का लागू किया जाना है। नि:शुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या बढ़ाई गई है। इसी क्रम में राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, पच्चीस जिलों में नर्सिंग कॉलेज, सातों संभागों में हेल्थ कॉलेज खोले जाने की घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू करने की भी घोषणा की गई है।

संवेदनशील और साहसिक

यह कटु-सत्य है कि कोविड महामारी की वजह से राज्य को विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे हालात में बजट में उद्योग के ढांचे को नया आकार देना, किसी तरह का कोई कर नहीं लगाना, बल्कि सभी वर्गों को लगभग 910 करोड़ रुपयों की राहत देना सराहनीय रहा। इनमें मुख्य रूप से डीएलसी और स्टांप ड्यूटी को

घटाना, यूज्ड दुपहिया वाहन एवं कारों के स्वामित्व हस्तांतरण पर एडिशनल मोटर व्हिकल टैक्स में छूट, किसानों को मंडी, कृषक कल्याण शुल्क एवं आढ़त घटाने, व्यापारियों को ई-वे बिल जारी करने की सीमा को एक लाख तक करने जैसे कदम शामिल हैं। प्रमुख बात यह भी रही कि कोरोना काल में करीब पांच लाख कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौती को भी वापस लेने की घोषणा की गई। इसे संवेदनशील सरकार का एक साहसिक कदम माना जा सकता है।

सर्वजन हिताय

इस क्रम में कई सरकारी नियमों और प्रावधानों में कई तरह की शिथिलताएं और रियायतें भी अलग से दी गई हैं। वहीं बजट में बालक, युवा, महिला, वृद्ध, विशेष योग्यजनों, समाज के विभिन्न वर्ग-सवर्ण, ओबीसी, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के तबकों को समान तवज्जो दी गई है। यही नहीं विकास के लिए जरूरी बजट का आवंटन इस तरह किया गया जिसमें प्रदेश के सभी संभागों, जिलों का संतुलित विकास हो सके, जो कि बजट का एक खूबसूरत पक्ष है।

नए कैडर गठन और समान पात्रता परीक्षा

बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के क्रम में चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर, संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने की घोषणा, विभागवार कैडर, समान पात्रता परीक्षा, सोशियल एंड परफोरमेंस ऑडिट अथॉरिटी, राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन, एसीबी में डिजिटल वॉयस लॉगर और छह नई नगरपालिकाओं का गठन किया गया है।

नये संस्थानों का गठन

वहीं नए संस्थानों के गठन के क्रम में आयुष अनुसंधान केंद्र, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेडिसिन एंड वॉयरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेटरनिटी एंड नियोनेटॉलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, डॉयरेक्टेट ऑफ फूड सेफ्टी, शांति एवं अहिंसा निदेशालय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड स्पेस क्लब, आर्चरी और हैंडबाल एकेडमी।

संभाग मुख्यालयों में समेकित बाल पुनर्वास केंद्र, जिला मुख्यालयों पर गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर संचालन केंद्र, वनधन केंद्रों, ग्रीन कॉरिडोर, कलाकार कल्याण कोष, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गठन किया गया है।

इन विभिन्न फैसलों से राजस्थान को देश में अग्रणी प्रदेशों की कतार में ला खड़ा करने की स्पष्ट ललक दृष्टिगोचर होती है।

जनकल्याण ही प्रतिबद्धता

जनकल्याण ही प्रतिबद्धता, जनकल्याण ही प्राथमिकता के प्रति मुख्यमंत्री का संकल्प बजट में दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं चुनौतियों का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने दृढ़ इरादे को '**उद्यमेन हि सिद्धयंति, कार्याणि न मनोरथै:**' से व्यक्त किया है।

अभिनव प्रयोगधर्मिता

अगले साल से राज्य का अलग से कृषि बजट, राज्य में मिलावट की रोकथाम के लिए पृथक से निदेशालय की स्थापना, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्तियों को पांच हजार के इनाम और प्रशस्तिपत्र देने से जुड़ी घोषणाओं को अभिनव प्रयोगधर्मिता की श्रेणी में गिना जा सकता है। वहीं किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 16 हजार करोड़ रुपये के ऋण, इनमें तीन लाख नए किसानों और मत्स्य एवं पशु पालकों को शामिल किया गया है। नयी कृषि विद्युत वितरण कंपनी के गठन का ऐलान किया गया।

रोजगारोन्मुखी बजट

बजट में दो साल में विभिन्न विभागों में पचास हजार सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा महत्त्वपूर्ण है। इन भर्तियों में कृषि विभाग में 1674, पशुपालन में 836, आयुर्वेद में 890, शिक्षा में 19 हजार, वन में 17 सौ, गृह में 8438, चिकित्सा शिक्षा में 336, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 5000, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी में 3838, पीडब्ल्यूडी में 1538, राजस्व में 11सौ तथा अन्य 8 हजार पदों पर भर्तियां होंगी।

नई नीतियों से मजबूत होगा आधारभूत ढांचा

वहीं बजट में प्रदेश के विकास के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए नई सड़क, ऊर्जा, आयुष, जलमिशन, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन, नए पर्यटन और धार्मिक सर्किट, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए नई नीतियां बनाने की घोषणाएं की गई हैं। संकटकालीन परिस्थितियों से जूझ रहे उद्योग एवं कारोबारों के विभिन्न सेक्टरों में विशेष छूट और सरकारी संबल देने की योजनाओं से उनमें प्राण फूंकने का प्रयास किया गया है। इनके जरिए रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे।

उद्योगों को दिया संबल

इसके अलावा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी, स्टार्टअप्स को सीड मनी, 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप, इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को पचास हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने, सहरिया, कथौड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणाएं प्रमुख हैं।

और निगाहों में मंजिल

सीमित आर्थिक संसाधन हैं। राह विकट है। विपरीत आर्थिक परिस्थितियां हैं। इसके बावजूद राजस्थान को अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने की मुख्यमंत्री की नजरें लक्ष्य अर्जन पर लगी हैं। यह चाह, उन्होंने स्वयं इन पंक्तियों में व्यक्त की है–

'निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे,

हवाओं ने कोशिश की, मगर चिराग अंधियारों में जलते रहे।'

कुल मिलाकर योजनाएं, नीतियां और विकास के प्रयासों का समय पर ठोस क्रियान्वन जरूरी है। सरकार को तेजी के साथ आर्थिक संसाधनों को जुटाने की भी जरूरत है। राजस्व वसूली में सक्रियता लाने और केंद्र से अपना बकाया वित्तीय हिस्सा लेने की भी जरूरत है।

संक्षेप में बजट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं–

कोरोना प्रबंधन– विशेष कोविड पैकेज की घोषणा

तैतीस लाख असहायों को दो हजार रुपये की सहायता। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 हजार नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी। स्टार्टअप्स को सीड मनी, 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप।

'बैक टू स्कूल कार्यक्रम' के तहत नि:शुल्क पोशाक व पाठ्यपुस्तकें, 470 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान। सहरिया, कथौड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा सुविधा। 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग कॉलेज। संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या में वृद्धि। राज्य के चिकित्सालयों में भवनों का निर्माण, चिकित्सा सुविधा व बेड क्षमता में वृद्धि। प्रदेश में 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। चिकित्सा संस्थानों को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत, 10 नवीन ट्रोमा सेंटर खोले जाएंगे। 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण, लगभग 206 करोड़ रुपए व्यय। कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना। विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1 हजार बेड्स की वृद्धि। 12 हजार चिकित्सा केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा। अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मॉडल सीएचसी। जिला अस्पताल, पावटा–जोधपुर की बेड क्षमता वृद्धि तथा आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 25 करोड़ 80 लाख रुपए व्यय। मेडिकल कॉलेज में नवीन आईसीयू, एनआइसीयू व जिला चिकित्सालयों में भी नवीन आइसीयू।

जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेडिसिन एंड वायरोजी व इंस्टिट्यूट ऑफ कॉर्डियोलॉजी की भी स्थापना। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार। जोधपुर में उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी की स्थापना

व रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना। 22 एडवांस लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस। 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालय, उदयपुर व जोधपुर में योग एंड नेच्यूरोपैथी कॉलेज। जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म। सभी जिला अस्पतालों में 8 विशिष्टताओं में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्सेज। विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर का गठन। डायरेक्ट्रेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाए जाने की घोषणा।

सड़क सुरक्षा

जीवन रक्षक योजना। इंटिग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। 40 सीएचसी को चिन्हित कर प्राइमरी ट्रोमा सेंटर। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान। नए जिला परिवहन कार्यालय तथा उप जिला परिवहन कार्यालय।

शिक्षा: ऑन लाइन शिक्षा को बढ़ावा

विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स, 82 करोड़ रुपये का व्यय। दो वर्षों में इंग्लिश मीडियम के 12 सौ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, 450 करोड़ रुपए की लागत।

शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना

जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज। जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। नवीन महाविद्यालयों एवं नवीन कन्या महाविद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालय, आईटीआई की स्थापना।

दिवंगत विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय

मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़, चूरू, कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर–भीलवाड़ा, किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुंवारिया, राजसमंद व भींडर–उदयपुर में गजेंद्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर में 200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। गेस्ट फेकल्टी हेतु विद्या संबल योजना। लगभग 1 हजार 500 राजकीय विद्यालयों में साइंस एंड स्पेस क्लब।

युवा एवं रोजगार

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना–2019 में बेरोजगार युवाओं को इंटर्रशिप व भत्ते को एक हजार रुपए से बढ़ाना। राजीव गांधी युवा कोर का गठन, ढाई हजार राजीव गांधी युवा मित्र, 50 हजार राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स।

समान पात्रता परीक्षा, वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम। परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा। आगामी दो वर्षों में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की योजना। मोरोली–भरतपुर में खेल स्टेडियम एवं काछवा–सीकर में भी खेल सुविधाएं। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा संभागीय मुख्यालयों पर खेलों के लिए बहुद्देशीय इंडोर हॉल। राजसमंद, सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम एवं प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम।

ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर लोकप्रिय खेलों के टूर्नामेंट्स, तीस करोड़ रुपये का प्रावधान। जोधपुर एवं जयपुर में नए रेजिडेंसियल स्पोर्ट्स स्कूल। बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर के सुदृढ़ीकरण कार्य, 20 करोड़ की लागत। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी।

कृषक एवं पशुपालक कल्याण

आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरूआत। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 16 हजार करोड़ रुपये के ऋण, 3 लाख नए किसान, मत्स्य पालक व पशुपालक सम्मिलित। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, 3 लाख किसानों को नि:शुल्क बॉयो फर्टिलाइजर्स एवं बॉयो एजेंट्स, तीन लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट, 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म की बीज। प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क, 200 करोड़ रुपये का व्यय। मथानिया–जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क। आंगणवा–जोधपुर में ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी 60 करोड़ रुपए का व्यय।

एक हजार किसान सेवा केंद्र, कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नए पद। किसानों को बिजली के लिए सब्सिडी 16 हजार करोड़ रुपए की लागत से अधिक का प्रावधान। नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी।

50 हजार किसानों को सोलर पंप तथा अन्य 50 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन। कृषि उपज मंडी समितियों में एक हजार करोड़ रुपए की लागत के कार्य। जोधपुर में किसान कॉम्पलेक्स पर 20 करोड़ की लागत। डूंगरपुर, हिंडौली व हनुमानगढ़ में 3 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना। चरणबद्ध रूप से एक हजार कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, 20 करोड़ रुपये की लागत। 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा, 48 करोड़ का व्यय। पशु चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार, 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों व 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत। प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन। राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह। नंदी शालाओं के लिए 111 करोड़ रुपए।

उद्योग

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए नई नीति। 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल

टाउनशिप की घोषणा, एक हजार करोड़ रुपये का निवेश। नया मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने के लिए 750 करोड़ रुपये।

जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। जयपुर में फिनटेक पार्क। जोधपुर में बॉयोटेक फार्मा बिजनेस इन्क्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर। रूरल आई-स्टार्ट।

सामाजिक सुरक्षा

राजस्थान पैटर्न। राजस्थान शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डवलपमेंट कानून। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, पांच हजार छात्र लाभांवित। 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के भवनों का निर्माण, 28 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय। 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण।

3 अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय। जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास। एससीएसटी ओबीसी व मायनोरिटी विकास कोष, प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए। देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का पैकेज, एमबीसी के लिए तीन छात्रावासों का निर्माण। डिनोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी। विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि। दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा युवाओं को दो हजार स्कूटी, 15 करोड़ रुपये व्यय। संभाग मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना। जिला मुख्यालयों पर गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन। 25 हजार आंगनबाड़ियों को नंद घर योजना में सम्मिलित करना।

महिलाओं के लिए

सभी महिलाओं को भी आवश्यकतानुसार सेनेटरी नेपकिन सुविधा, 200 करोड़ रुपये का प्रावधान। जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना, 15 करोड़ का प्रावधान। जनजाति क्षेत्रों में 250 मां-बाड़ी केंद्र। 150 वनधन केंद्रों का गठन। वीरांगनाओं एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को देय सम्मान भत्ता 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार प्रतिमाह। देवस्थान विभाग के पुजारियों के मानदेय में वृद्धि।

सड़क-शहरी विकास

नवीन राज्य सड़क नीति-2021। कुल एक हजार करोड़ रुपये की राशि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पेचेबल या मिसिंग लिंक सड़क के कार्य। सभी जिलों में 7 हजार 257 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का क्रमोन्नयन। प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग 1900 करोड़ रुपए लागत से। नगर निगमों

की 30 किलोमीटर, नगर परिषदों की 20 किलोमीटर व नगर पालिकाओं की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य।

आगामी दो वर्षों में 2 हजार 841 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों पर 1 हजार 425 करोड़ खर्च। 3 हजार 880 करोड़ रुपये की लागत से 27 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य। 403 करोड़ रुपये की लागत से 8 आरओबी का निर्माण। 8 रेल फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए डीपीआर। बूंदी जिले में हाइलेवल ब्रिज, 37 करोड़ 50 लाख की लागत। कोटा जिले में हाइलेवल ब्रिज के निर्माण के लिए डीपीआर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लगभग 3 हजार आवासों का निर्माण। बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण।

जयपुर शहर में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य। भरतपुर शहर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम, लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय। कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए विभिन्न निर्माण कार्य, 140 करोड़ रुपये। जोधपुर शहर में लूपिंग रूट, हेरिटेज संरक्षण का कार्य, 100 करोड़ रुपये का व्यय। बीकानेर में सड़कों के विभिन्न निर्माण कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपये। उदयपुर शहर में विभिन्न निर्माण आदि कार्य पर 150 करोड़ रुपये। जोधपुर में 60 करोड़ रुपये से आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का निर्माण। दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवं बूंदी में टाउनहॉल। ग्रामीण बस सेवा पुन: आरंभ, लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को लाभ।

पेयजल–जल संसाधन

जल जीवन मिशन में लगभग 4 हजार 700 करोड़ रुपये की 12 वृहद् पेयजल परियोजनाओं का काम, 1 हजार 428 गांव एवं 1 हजार 891 ढाणियां लाभांवित। जल जीवन मिशन में 2 हजार 285 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे 2 हजार 686 गांव और 2 हजार 453 ढाणियां लाभांवित। जल जीवन मिशन में लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन।

जल जीवन मिशन के तहत 22 परियोजनाओं की डीपीआर। विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत 476 करोड़ रुपये के कार्य। चंबल–भीलवाड़ा पेयजल परियोजना–1 हजार 32 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्य प्रारंभ। नोखा–बीकानेर पेयजल परियोजना–750 करोड़ रुपये की परियोजना का कार्य प्रारंभ। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए आगामी वर्ष में 7 हजार 700 करोड़ के कार्य। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल। जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं में पेयजल की सुचारू व्यवस्था के लिए लगभग 76 करोड़ रुपये व्यय।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कार्य के लिए 320 करोड़ का प्रावधान। परवन वृहद् सिंचाई परियोजना पर 885 करोड़ का प्रावधान। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर 465 करोड़ रुपये खर्च, 21 जिले लाभांवित। रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अंतर्गत लगभग 378 करोड़ रुपये के जीर्णोद्धार कार्य। रिपेयर–रिनोवेशन–रेस्टोरेशन योजना में 124 करोड़ 71 लाख रुपये के 37 कार्य।

ऊर्जा

ऊर्जा नीति: 2021–2050। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का ग्रीन कॉरिडोर।

वन एवं पर्यावरण

सामुदायिक वन अधिकार पट्टे के लिए अभियान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को वेटलैंड बर्ड्स हेबिटेट कंजरवेशन सेंटर के रूप में विकसित करना। तालछापर अभयारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र। जोधपुर में 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन'। 24 जिलों के 50 शहरों में एफएसटीपी, दो सौ करोड़ रुपये का व्यय। प्रदेश के बड़े अस्पतालों में 25 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान। शेखावाटी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। आरटीडीसी द्वारा संचालित 7 मिडवे का 10 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार। प्रमुख तीर्थस्थलों का धार्मिक पर्यटन सर्किट, 100 करोड़ रुपये की लागत। पुष्कर–अजमेर में टूरिस्ट कॉम्पलेक्स। जैसलमेर में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्पलेक्स की डीपीआर, राजस्थान फोक ऑर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना। कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान दिवस पर 'राजस्थान उत्सव' का आयोजन। 5 हजार प्रतिभाशाली युवाओं, कलाकारों एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए नेहरु यूथ कल्चरल एक्सपोजर प्रोग्राम।

कानून व्यवस्था

इंटर ओपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रभावी रूप से लागू। नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय। पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नयन, 25 नवीन पुलिस चौकियां। जयपुर आयुक्तालय में तीन नवीन थाने बनाए जाएंगे। राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉरपोरेशन। जेलों में बुनियादी सुविधाओं संबंधी कार्य, लगभग साढ़े इकत्तीस करोड़ की लागत। एसीबी में डिजिटल वॉयस लॉगर की स्थापना। प्रदेश में विभिन्न 40 नये न्यायालयों की स्थापना।

सुशासन

सोशल एंड परफोरमेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन। नए एडीएम, नवीन उपखंड, तहसील, उपतहसील कार्यालय। सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय। 6 नई नगरपालिकाओं का गठन। भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में लेटरल एंट्री, लगभग 5 हजार भूतपूर्व सैनिकों को लाभ। 1 मई 2021 से प्रशासन गांवों के संग तथा 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान। 3 हजार करोड़ रुपये की राशि से कार्मिक कल्याण कोष। 10 करोड़ रुपये की राशि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता के रूप।

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा। कोरोना के कारण डेफर किए गए वेतन को जारी करने की घोषणा। संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने की घोषणा, विभागवार केडर। एचसीएम आरआइपीए, जयपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम।

कर–प्रस्ताव

राज्य के उद्यमी, रियल एस्टेट व्यवसायी, पर्यटन इकाइयां, व्यापारी, किसान, आमजन के साथ–साथ राज्य सरकार के राजस्व पर कोविड 19 से विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार को वर्ष 2020–

21 में जनवरी, 2021 तक के बजट अनुमानों से 32 फीसदी राजस्व कम मिला है। वर्ष 2020–21 में केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले कर राजस्व हिस्से में राज्य को 14 हजार करोड़ 94 लाख रुपये कम प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद बजट 2021–22 में कोई नया कर नहीं लगाया गया है एवं सभी वर्गों को लगभग 910 करोड़ रुपये की राहत दी गई है।

आमजन

यूज्ड दुपहिया वाहन एवं कारों के स्वामित्व हस्तांतरण पर एडिशनल मोटर व्हीकल टैक्स में 50 फीसदी छूट। ई–व्हीकल्स के क्रेता को एसजीएसटी का पुनर्भरण एवं दुपहिया व तिपहिया ई–व्हीकल्स की खरीद पर अनुदान। स्थानीय निकायों तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी, डीएलसी के बजाय एलोटमेंट राशि पर ली जाएगी।

14 जुलाई 2014 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी डीएलसी का 40 फीसदी लिया जाएगा। पैतृक संपत्ति के हकत्याग पर स्टांप ड्यूटी मुक्ति का दायरा बढ़ाया। पुत्रियों के समान पुत्रवधुओं के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर 2.5 के स्थान पर 1 फीसदी स्टांप ड्यूटी। पोता–पोती, दोहिता–दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टांप ड्यूटी से मुक्ति। मद्यसंयम के लिए स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा जन जागरुकता अभियान।

हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों का पुनर्वास, बच्चों की शिक्षा तथा नशामुक्ति के लिए सौ करोड़ रुपये से नवजीवन कोष।

राजस्व अर्जन विभागों में स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का रिफंड, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट एवं परमिट आदि का सरलीकरण कर ऑन लाइन जारी किए जाएंगे।

सिक्योरिटी बॉण्ड पर देय स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये की जाएगी। ऋण दस्तावेज पर बकाया स्टांप ड्यूटी के मामलों के लिए 1 अप्रैल 2021 से नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी।

मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं आढ़त को घटाकर किसानों को राहत। कोलोनाइजेशन एरिया के सभी श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की 30 जून 2021 तक बकाया समस्त किश्तों पर ब्याज माफी तथा समस्त बकाया किश्तें जमा कराने पर मूल बकाया राशि में भी 10 फीसदी छूट।

आरआइपीएस–2014 की कार्यावधि को 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक। लैंड टैक्स पर ब्याज एवं शास्ति में छूट की तिथि 30 जून 2021 तक। जेम्स एंड ज्वेलरी ब्रूस को आरआइपीएस–2019 के सेवा क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। ●

फार्म–1

(नियम 3 देखिये)

1.	समाचार पत्रिका का नाम	:	राजस्थान सुजस
2.	समाचार पत्रिका की भाषा	:	हिन्दी
3.	प्रकाशन का स्थान	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर
4.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
5.	मुद्रक का नाम	:	महेन्द्र सोनी
	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
	पता प्रेस	:	मैसर्स रैनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स बाईस गोदाम, जयपुर मैसर्स प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, बाईस गोदाम, जयपुर मैसर्स पॉपुलर प्रिन्टर्स, एम.डी. रोड़, जयपुर मैसर्स प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, रामनगर सोडाला, जयपुर
7.	सम्पादक का नाम	:	डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
	पता	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सचिवालय, जयपुर

8. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं, महेन्द्र सोनी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

महेन्द्र सोनी

देश का
25%
टीकाकरण अकेले
राजस्थान में

कोविड टीकाकरण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5 मार्च को सवाई मानसिंह अस्पताल के आईडीएच सेंटर पहुंचकर कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भी टीका लगवाया।

वैक्सीनेशन के बाद श्री गहलोत ने अस्पताल में कोविड क्रिटिकल केयर यूनिट का दौरा कर वहां इन्फेक्शियस आईसीयू, एडवांस आइसोलेशन केयर यूनिट और लैब आदि का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद चिकित्साकर्मियों, नर्सिंगकर्मियों एवं अन्य स्टाफ की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में आपने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा का जो फर्ज निभाया है, वह सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। वैक्सीनेशन से कोरोना संक्रमण की रोकथाम का काम और मजबूती से हो सकेगा। कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। अब तक हुए टीकाकरण में ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है, जिसमें टीकाकरण के कारण कोई गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिला हो। राजस्थान ने जिस सफलता के साथ कोरोना का प्रबंधन किया, उसी उत्साह और सभी वर्गों की भागीदारी से टीकाकरण अभियान भी कामयाबी से संचालित हो रहा है। राज्य में प्रतिदिन दो से सवा दो लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। देश का करीब 25 प्रतिशत टीकाकरण अकेले राजस्थान में हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपील की है कि टीकाकरण अभियान के शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी लोग आगे बढ़कर टीका लगवाएं। तीसरे चरण के तहत 60 वर्ष और इससे अधिक आयु तथा 45 वर्ष से अधिक के को-मोर्बिड व्यक्ति टीकाकरण अवश्य कराएं। यह हम सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों में कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़े हैं। हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना को लेकर सजगता और सतर्कता के साथ रहना होगा। असावधानी के कारण हम कोरोना की जीती हुई जंग नहीं हार जाएं, इसके लिए हमें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य प्रोटोकॉल की निरंतर पालना करनी चाहिए।

विधानसभा में कोविड टीकाकरण का विशेष शिविर

राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी की पहल पर पंद्रहवी विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई। इसके लिए विधानसभा परिसर में चिकित्सकों के दल व स्टाफ ने टीकाकरण व टीकाकरण के बाद ऑब्जर्वेशन की पूरी व्यवस्था की। विधानसभा में कोविड टीकाकरण के लिए लगाए गए इस विशेष शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी व विधायकगण ने कोविड का टीका लगवाया।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार न जाएं इसलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं

प्रिय प्रदेशवासियों,

कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देश के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में कोरोना वापस तेजी से फैल रहा है। छोटी-सी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर खतरा अभी टला नहीं है। यूके, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का नया स्ट्रेन भी सामने आया है। जब तक कोरोना की चैन पूरी तरह नहीं टूटेगी, तब तक खतरा बरकरार रहेगा। हम सबने कोरोना का सबसे कठिन दौर देखा है। सरकार की ओर से शादी-समारोह, व्यवसाय, शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों के लिए दी गई छूट आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन लापरवाही का व्यवहार कोरोना संक्रमण बढ़ा सकता है। ऐसी कोई भूल न दोहराएं, जिससे फिर क्वारंटीन और आइसोलेशन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़े या लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो।

कोरोना से जंग में ढिलाई नहीं बरतनी है। भीड़ से बचने, मास्क लगाने, हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करना है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, उनको भी वैक्सीनेशन और सावधानियां रखने की जरूरत है। फिर भी किसी में कोरोना के लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें।

वैक्सीन सुरक्षित है, प्राथमिकता क्रम से बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं व आस-पास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। हमें किसी भी कीमत पर कोरोना से जीती हुई जंग को नहीं हारना है। सावधानियों का पालन करने के सामूहिक संकल्प से ही यह संभव है।

(अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री)

पहनिए मास्क

धोइए हाथ

रखिए दो गज दूरी

किसी भी सहायता हेतु 181 पर सम्पर्क करें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, महेन्द्र सोनी द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक– डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा • मैसर्स प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, सी–4, बाईस गोदाम, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 60,000 प्रतियां